

अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था (Economics and Economy)

➤ अर्थव्यवस्था (Economy)

- सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। उनकी पुस्तक *Wealth of Nation* 1776 में प्रकाशित हुई। उन्होंने कर का सिद्धांत दिया। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य / कौटिल्य अथवा विष्णु गुप्त को कहते हैं एवं उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी, जिनका प्रयोग प्रशासन हेतु किया जाता

था। भारतीय आर्थिक नीति के जनक **M. Visves Varaya** को कहते हैं एवं उन्होंने **Planned Economy for India** नामक पुस्तक लिखी।

➤ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र

- अर्थव्यवस्था में आय के माध्य को क्षेत्र कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटते हैं।



आर्थिक क्रियाओं के आधार पर

1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

- जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं एवं इसमें भूमि, उत्खनन तथा उससे संबंधित गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

Ex :- कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन।

- जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें लाल कॉलरधारी कहते हैं।

2. द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector)

- इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है एवं यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तुओं (उपयोग हेतु) में परिवर्तित करता है।

Ex :- वस्तु, उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, विद्युत इत्यादि।

- जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें नीली कॉलरधारी कहते हैं।

3. तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)

- इसमें नौकरी, व्यापार, दुकान को शामिल करते हैं। इसे 'सेवा क्षेत्र' भी कहते हैं।

Ex :- परिवहन, Hospital, कोचिंग, नेता, खेल, Communication, Bank, शिक्षा, नौकरी।

- जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें सफेदपोश श्रमिक कहते हैं।

Note :- सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं। किन्तु आय बहुत अधिक होती है। जैसे-जैसे लोगों का विकास होता जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीयक क्षेत्र में चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय (2022) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 21.82%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 24.23% तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 53.09% है।

कार्य के आधार पर

1. संगठित क्षेत्र

- जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हो उसे 'संगठित क्षेत्र' कहते हैं।

Ex :- बड़े कम्पनी की नौकरी, सरकारी नौकरी।

- संगठित क्षेत्र में सार्वधिक रोजगार रेलवे तथा सेना में दिया है।

2. असंगठित क्षेत्र

- इसमें नौकरी का समय वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहता है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग है।

Ex :- प्राइवेट क्षेत्र, कृषि, दुकान।

स्वामित्व के आधार पर

1. निजी क्षेत्र (Private Sector)

- इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। इसे Private (Pvt.) कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। पूंजी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी Private कम्पनी Reliance जबकि कर की क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कम्पनी TATA है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)

- इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। इसे Public sector भी कहते हैं यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी Public क्षेत्र की कम्पनी रेलवे तथा महारत्न है।

3. संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector)

- इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है। अतः इसे public private patnership कहते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से ppp का विकास हो रहा है। उदाहरण- मेट्रो

4. सहकारी क्षेत्र (Co-operative Sector)

- जब किसी कम्पनी को दिशा निर्देश सरकार देती है उसे co-operative कहते हैं।

Ex :- Co-operative Bank co-operative का संचालन कई लोगों के समुह द्वारा होता है।

उत्पादन के चार कारक

1. पूँजी

- उत्पादन में लगाया गया धन पूँजी कहलाता है यह ऋण के रूप में भी हो सकता है।

2. भूमि

- जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहते हैं। यह किराया के स्थान पर भी हो सकता है।

3. श्रमिक

- वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं।

4. उद्यमी

- कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं।



संसाधनों के स्वामित्व या उत्पादन के साधन
या सरकार की भूमिका के आधार पर

पूँजीवादी

- ❖ अहस्तक्षेप (बाजार शक्तियाँ-मांग व आपूर्ति) व निजी स्वामित्व
- ❖ अमेरिका, कनाडा आदि।

समाजवादी

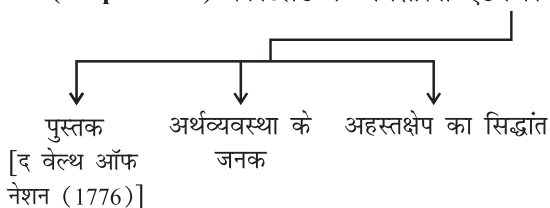
- ❖ सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व
- ❖ क्यूबा, उत्तर कोरिया आदि
- ❖ इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।

मिश्रित

- ❖ सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता
- ❖ भारत, स्वीडन, फ्रांस आदि।

पूँजीवाद अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

प्रस्तुतकर्ता (Propounded)-स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ।



- इन्होंने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था

- जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जापान, U.S.A., सिंगापुर, चीन, पूँजी, अर्थव्यवस्था में विकास तेजी

विशेषता- प्रतिस्पर्धा।

उद्देश्य- अधिकतम लाभ।

आर्थिक स्वतंत्रता।

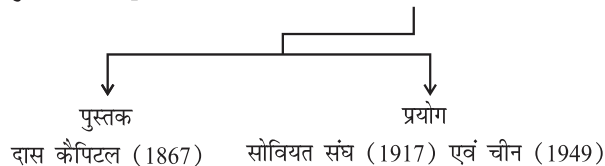
उपभोक्ता के पास विकल्प।

आर्थिक समानता।

से होता है। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

प्रस्तुतकर्ता (Propounded)– जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (1818-1883)



विशेषता–

उद्देश्य– जनकल्याण।

बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव।

केन्द्रीय आर्थिक नियोजन।

बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत।
आर्थिक समानता।

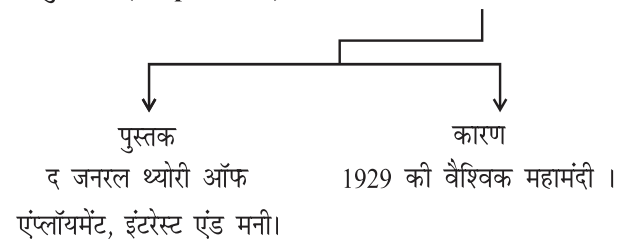
➤ समाजवादी अर्थव्यवस्था

- जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएँ (उत्पादन, उपभोग, वितरण व विनिमय) को संचालित करती है।

उदाहरण– सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

प्रस्तुतकर्ता (Propounded)– ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कोस।



➤ मिश्रित अर्थव्यवस्था

- जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूँजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है।

Ex :- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका।

➤ द्वैध अर्थव्यवस्था (Dual Economy)

- वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परम्परागत तथा आधुनिक दोनों विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं।

Ex :- India.

➤ समांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy)

- कालाधन अत्यधिक बढ़ जाने को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी होती हैं।

➤ काला धन (Black Money)

- वैसा धन जिस पर Tax नहीं दिया जाता है उसे कालाधन कहते हैं। कालाधन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है।

विशेषता–

उद्देश्य– जनकल्याण।

कल्याणकारी राज्य।

आर्थिक नियोजन।

सामाजिक न्याय।

□□□

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

02.

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (Gross Domestic Products)

➤ सकल घरेलू उत्पाद [GDP (Gross Domestic Products)]

- एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के मूल्य को GDP कहते हैं। सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को G.D.P. में शामिल नहीं किया जाता है।

जैसे— tata = 800 Man (विदेशों में भारतीय) = 150
L. G = 300 GDP = 1100

➤ सकल राष्ट्रीय उत्पाद [GNP (Gross National Products)]

- यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। इसमें केवल भारतीय आय को शामिल करते हैं।

माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय x है, तथा विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय y है, तो—

$$\boxed{\text{GNP} = \text{GDP} (x + y)} \quad \text{Ram} = 150$$

tata = 800

L.G = 300

$$\text{GNP} = 1100 + (150 - 300) = 950$$

Note : $x - y$ को शुद्ध साधन आय कहते हैं।

Case I : यदि $x = y$ हो (संतुलित अर्थव्यवस्था) $\text{GNP} = \text{GDP}$

Case II : यदि $x > y$ हो (लाभ) $\text{GNP} > \text{GDP}$

Case III : यदि $x < y$ (हानि) $\text{GNP} < \text{GDP}$

Case IV : यदि $x = y = 0$ (बन्द अर्थव्यवस्था) $\text{GNP} = \text{GDP}$

Q. GDP तथा GNP का अंतर क्या कहलाता है।

Ans. $\text{GDP} - \text{GNP}$

$$\text{GDP} - (x + y)$$

$$(x - y) = \text{शुद्ध साधन आय}$$

➤ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन [NNP (Net National Products)]

- यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब GNP में से मशीनों की टुट-फुट या घिसावट पर आय खर्च को घटा देते हैं, तो उससे NNP मिलता है।

$$\boxed{\text{NNP} = \text{GNP} - D} \quad \text{जहाँ } D = \text{मूल्यहास}$$

tata = 800 Ram = 150

L.G = 300 D = 50

GDP = 1100

GNP = 950

$$\text{NNP} = 950 - D = 950 - 50 = 900$$

Q. GNP तथा NNP का अंतर क्या होता है?

Ans. $\text{GNP} - \text{NNP}$

$$\text{GNP} - (\text{GNP} - D)$$

$$\text{GNP} - \text{GNP} + D$$

$D = \text{मूल्यहास}$

- किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्य प्रति व्यक्ति आय होता है।
- किसी देश के प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम GDP होता है।
- मूल्य के आधार पर भारत की GDP छठे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका।
- किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत (factor cost) पर निर्भर करती है। कोई भी वस्तु अपने Factor Cost पर बनी रहती है।

$$\text{Price} = \text{Factor Cost (F.C.)}$$

$$\text{MRP} = \text{FC (Factor Cost)} + \text{TAX}$$

$$\boxed{\text{GDP at Market Price (GDP}_{(\text{MP})})}$$

- GDP हमेशा Market Price पर ही निकलता है।

➤ $\text{GDP}_{(\text{MP})}$

- जो Price हमें मिलता है उसमें सरकार द्वारा Tax जोड़कर महंगा कर दिया जाता है या सब्सिडी जोड़कर सस्ता कर दिया जाता है।

$$\text{GDP}_{(\text{MP})} = \text{GDP}_{(\text{FC})} + \text{Tax} - \text{Subsidies}$$

$$\boxed{\text{GDP at Factor Cost (GDP}_{(\text{FC})})}$$

- वास्तविक में GDP की गणना Factor Cost पर ही होनी चाहिए।

$$\text{GDP}_{(\text{FC})} = \text{GDP}_{(\text{MP})} - \text{Tax} + \text{Subsidies}$$

हम जो GDP निकालते हैं Actual में वह Nominal GDP न होकर Real GDP होता है जो किसी न किसी Base Year पर निर्भर करता है।

➤ Nominal GDP

- इसमें उत्पादित वस्तु का चालू वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है।
- जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों (चालू कीमतों) पर की जाती है तो उसे Nominal GDP कहते हैं।
- Nominal GDP हमेशा अधिक होती है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ी होती है।
- Nominal GDP में Production Value नहीं देख पाते हैं।
- Nominal GDP उस साल के Price पर निकाला जाता है जिस साल की GDP को निकाल रहे हैं।

Pencil	Per Pencil Price	Production	Nominal GDP
2011	5	20	$5 \times 20 = 100$
2012	6	19	$6 \times 19 = 114$
2020	7	18	$7 \times 18 = 126$
2021	10	15	$10 \times 15 = 150$
2022	15	14	$15 \times 14 = 210$

$$\text{Purchasing Power Parity Formula} = \frac{\text{Cost of good} \times \text{in currency 1}}{\text{Cost of good} \times \text{in currency 2}}$$

□□□

Real GDP

- जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य (स्थिर कीमतों) पर की जाती है तो उसे Real GDP कहते हैं।
- इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की सही एवं अधिक वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है।
- जब हम Real GDP को निकालते हैं तो Price हम आधार वर्ष का लेते हैं और Production चालू वर्ष का लेते हैं।
- Base Year = 2011

$$\text{GDP Deflector} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

Pencil	Per Pencil Price	Production	Nominal GDP	Real GDP
2011	5	20	$5 \times 20 = 100$	$5 \times 20 = 100$
2012	6	19	$6 \times 19 = 114$	$5 \times 19 = 95$
2020	7	18	$7 \times 18 = 126$	$5 \times 18 = 90$
2021	10	15	$10 \times 15 = 150$	$5 \times 15 = 75$
2022	15	14	$15 \times 14 = 210$	$5 \times 14 = 70$
			GDP = ↑	GDP = ↓

क्रय शक्ति समर्थ (Purchasing Power Parity)

- यह अंतराष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है।
- यह देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर है।
- किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है।
- PPP के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर या फिर कितना समता मौजूद है।
- PPP द्वारा मुद्रा विनिमय दर को तय किया जाता है।
- PPP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। प्रथम तथा दूसरे स्थान पर चीन अमेरिका है।
- भारत का PPP और अमेरिका के PPP में 17 गुना का अंतर है।
India = US × 17

राष्ट्रीय आय (National income)

- किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी से मिलने वाली कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर NNP होता है।

राष्ट्रीय आय = NNP – अप्रत्यक्ष कर

- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी स्थापना 1951 में हुई। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो P.C महालनोबिस का जन्म दिवस है।
- भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना 1968 में दादाभाई नौरोजी ने किया। उन्होंने इस समय भारत का प्रतिव्यक्ति आय ₹ 20 निकाला था, जो सालाना था। इन्होंने अपनी पुस्तक Poverty and Unbritish Rule in India में लिखी है।
- वर्तमान में भारत का प्रतिव्यक्ति आय 1 लाख 72 हजार सालाना है। किसी देश के प्रगति को दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय होता है।

$$\text{प्रतिव्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$$

➤ हिन्दू विकास दर

- हिन्दू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है।

➤ चालू कीमत

- चल रहे वित्तीय वर्ष को चालू कीमत कहते हैं। इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं निकलता है।

➤ स्थिर कीमत

- बीते हुए वर्ष पर निकाला गया राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है। इसके लिए किसी वर्ष को हम आधार मान लेते हैं। भारत का आधार वर्ष 2017-18 है।
- राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर NNP को दर्शाता है।

➤ राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ हैं-

1. उत्पादन विधि

- इस विधि में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। यह GDP को दर्शाता है। इसमें दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस कारण अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है।

$$\text{उत्पादन} \rightarrow \text{NNP}_{(fc)} = \text{NNP}_{(mp)} - \text{Tax} + \text{Subsidy}$$

2. आय गणना विधि

- इस विधि द्वारा सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है। चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन तथा आय दोनों विधि से किया जाता है।

$$\text{NI} = \text{R} + \text{I} + \text{W} + \text{P}$$

आय विधि → भूमि = किराया (R)
पूँजी = ब्याज (I)
श्रम = मजदूरी (W)
उद्यम = लाभ (P)

3. व्यय विधि (Expenditure Method)

$$\text{N.I.} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{x} - \text{m})$$

C = उपभोग

I = निवेश

G = सरकारी व्यय

x = Export

m = Import

(x - m) = शुद्ध निर्यात (Net Export)

4. उपभोग विधि

- इस विधि में उपयोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है। बचत विधि तथा मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है।

5. सकल मूल्यवर्धन विधि

गेहूँ	Value Added +500	आटा	Value Added +500	बिस्किट
100 kg		100 kg		1000 Packet
20 Rs.		25 Rs.		5 Rs.
Value 2,000		2,500		5,000

$$\text{N.I.} = 2,000 + 2500 + 5000 = 9500 \text{ Rs.} \times$$

$$\text{N.I.} = \text{Primary Value} + \text{Value added} + \text{value Add} \\ = 2000 + 500 + 2500 = 5000 \checkmark$$

➤ मौद्रिक आय

- किसी श्रम के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं।

➤ प्रयोज्य आय (Disposable income)

- मौद्रिक आय में से tax घटाने के बाद बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह White money होता है।

➤ वास्तविक आय (Real income)

- प्रयोज्य आय में से देनदारी तथा ऋणभार को हटा देने पर बचा हुआ धन वास्तविक आय कहलाता है। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है।

Q. नितिश ने अनुराधा से ₹ 4000 कर्ज लिये। यदि नितिश की आय ₹ 1 लाख है तथा नितिश पर 30% tax है। इसके सभी आय की गणना किजिए।

Ans. मौद्रिक आय = 1 लाख

$$\text{प्रयोज्य आय} = 1 \text{ लाख} \times 30\% = 70,000$$

$$\text{वास्तविक आय} = 70,000 - 4000 = 66,000 \text{ Ans.}$$

गरीबी (Poverty)

☞ गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाये रखने में आवश्यक है।

गरीबी में पाँच मूलभूत चीजों में से एक या एक से अधिक की कमी से हो जाती है—

- (i) भोजन
- (ii) वस्त्र
- (iii) आवास
- (iv) शिक्षा
- (v) चिकित्सा।

➤ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार

☞ गरीबी निम्नतम जीवन-यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन-यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके।

➤ विश्व बैंक के अनुसार

☞ वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय 2 अमेरिकी डॉलर से कम है, वह गरीब है।

➤ वी.एम. और एन. रथ फार्मूला (1971)

☞ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि।

➤ सुरेश तेंदुलकर समिति (2009)

☞ इसमें कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया गया।

☞ शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रति दिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिये 27 रुपये प्रति दिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं।

➤ सी. रंगराजन समिति (2012)

☞ शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रति दिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिये 32 रुपये प्रति दिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistical Office (NSO)]

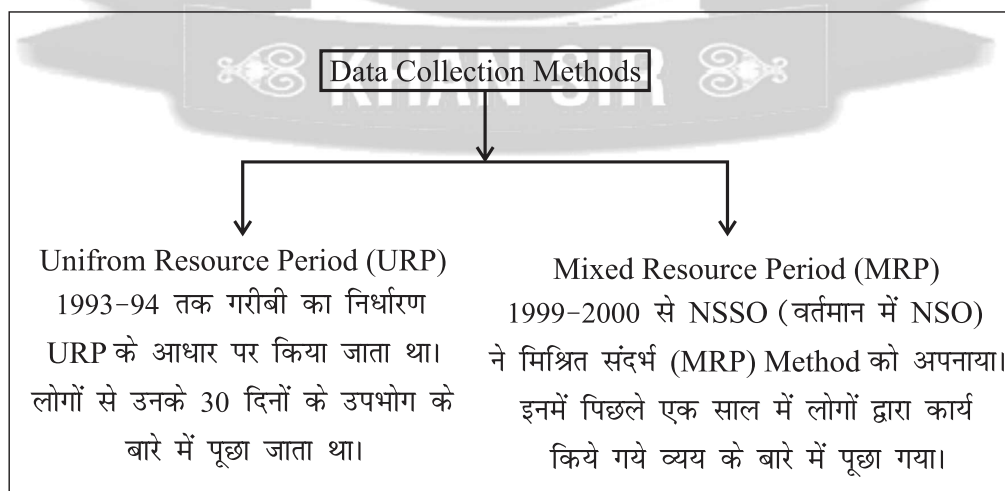
☞ 2019 में NSSO और CSO के विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) का गठन हुआ। 2019 से पहले भारत में गरीबी का अनुमान NSSO द्वारा किया जाता था। जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था, जो केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन था।

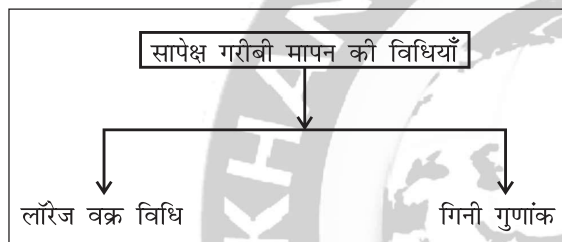
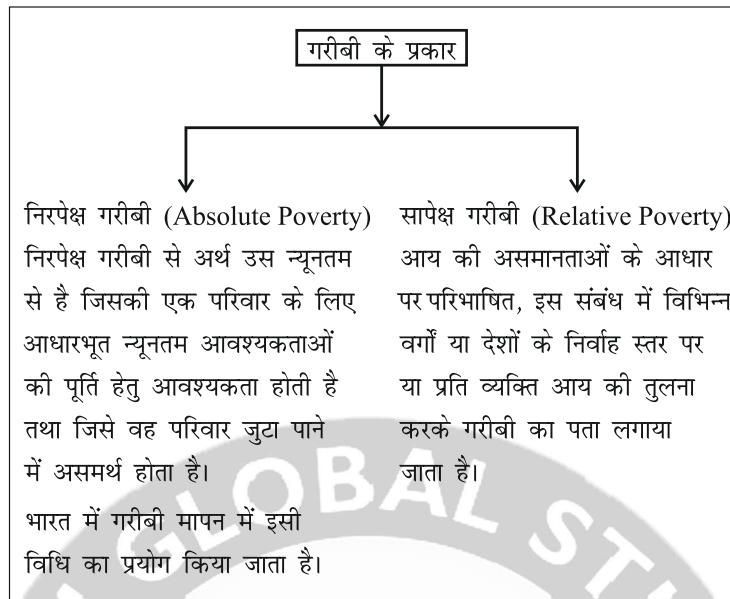
केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

नीति आयोग

Data Collection Methods



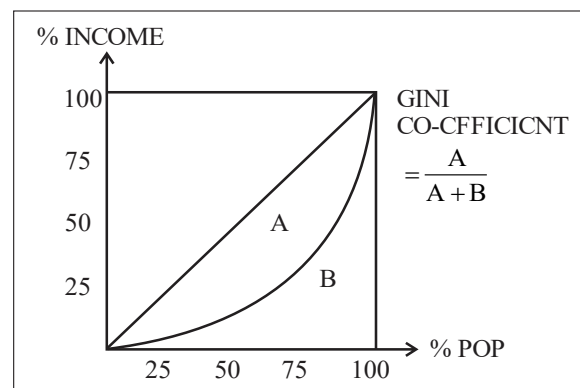
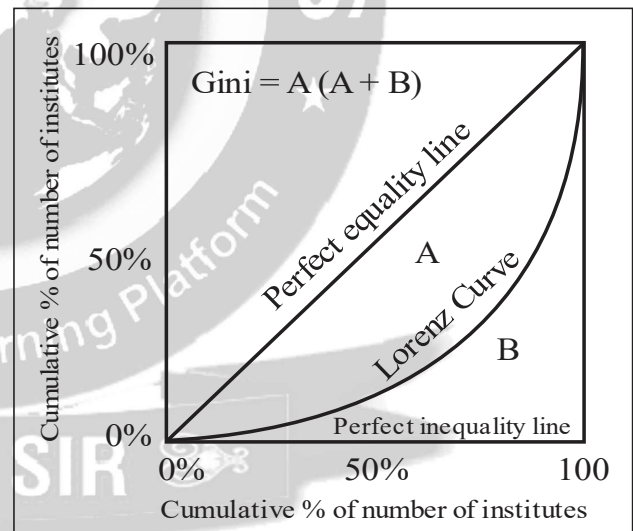
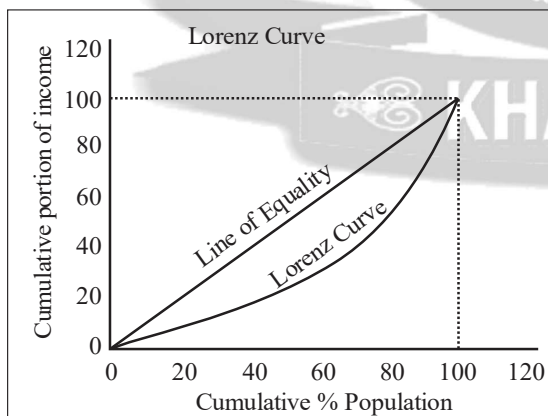


- यह आय में वितरण की विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि है।
- आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करता है।

$$\text{गिनी गुणांक} = \frac{\text{छायांकित क्षेत्रफल}}{\text{समता रेखा के नीचे का सम्पूर्ण क्षेत्रफल}}$$

लॉरेंज वक्र विधि

- 1905 में मैक्स ओ. लॉरेंज ने विकसित किया था।
- इस विधि द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं।
- इस वक्र का प्रत्येक बिन्दु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं।



गिनी गुणांक

- 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया था।

- भारत में योजना आयोग द्वारा बनाए गए गरीबी मापन हेतु प्रमुख समितियाँ-

समितियाँ	वर्ष
डॉ. वाई.के. अलघ समिति	1977
लकड़ावाला समिति	1989
सुरेश तेंदुलकर समिति	2005
सी.रंगराजन समिति	2012

बेरोजगारी (Unemployment)

- बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समय पर उसके योग्यता अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगारी के कई स्वरूप होते हैं। इससे संबंधित आंकड़े NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं।
- बेरोजगारी को दर्शाने के लिए फिलिप्स वक्र का प्रयोग किया जाता है।
- संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)**
 - जब मांग में परिवर्तन हो और मांग में संरचनात्मक बेरोजगारी की कमी हो जाए तो इससे उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह दीर्घकालीन होता है। अस्फिति (धन की कमी) के कारण यह संचालक या ढाचागत बेरोजगारी उत्पन्न करती है। भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है।
- चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)**
 - जब मांग पुरी तरह समाप्त हो जाए अर्थात् समग्र मांग की अभाव में फैक्ट्री बंद जाए तो उससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार होते हैं।

- चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः व्यापार चक्र से संबंधित होती है तथा यह अस्थायी प्रकृति की होती है।

Ex :- NOKIA/FACTORY → परिवहन → DEALER Distributer → Wholesaller → Retailer → उपभोक्ता

- घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)**
 - जब तकनीकी विकास होता है तो पुराने तकनिक के लोग तब तक के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। जब तक कि वो नई तकनिक सिख नहीं जाते हैं। अर्थात् नई नौकरी को खोजने के दौरान हुई बेरोजगारी घर्षणात्मक होती है। यह अल्पकालीन होती है। यह भारत के शहरी क्षेत्र में देखी जाती है।
- छिपी बेरोजगारी/अदृश्य/प्रच्छन्द (Disguised Unemployment)**
 - वह बेरोजगारी जिसमें मजदूर काम पर लगा हुआ तो दिखता है किंतु उसकी उत्पादकता (सिमांत उत्पादकता) शून्य होती है। अर्थात् उसे नौकरी से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि क्षेत्र में यही बेरोजगारी देखी जाती है।
- मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)**
 - वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है।
- Ex :- फसल कटाई के बाद किसान ठंडी में जुस का कार्य।
- शिक्षित बेरोजगारी (Educational Unemployment)**
 - जब किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इसमें मजदूर अपनी कुल क्षमता से कार्य नहीं करता है।
- Note :- ओकून का नियम (Okun's Law)- यह नियम किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। यह दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है।

□□□

KHAN SIR

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

राष्ट्रीय नियोजन (National Planning)

- ☞ संसाधनों के उचित उपयोग के लिए सरकार नियोजन (प्लानिंग) करती है। भारत में नियोजन का इतिहास योजना आयोग से भी पुराना है।
- ☞ भारत में सर्वप्रथम 1934 ई. में एम. विश्वेश्वरैया की पुस्तक *Planned Economy of India* में योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी।
- ☞ यह योजना 10 वर्षीय थी। जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दोगुना करना तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था।
- ☞ इसके पश्चात् 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। इसे 'कांग्रेस योजना' भी कहा जाता है।
- ☞ वर्ष 1944-45 में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक प्लान बनाया गया जिसे 'बांबे प्लान' कहा गया।
- ☞ वर्ष 1944 में श्रीमन् नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी विचारधारा के रूप में गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया। जिसमें कृषि क्षेत्र एवं लघु, कुटीर औद्योगिक विकास पर बल दिया।
- ☞ वर्ष 1945 में एम.एन. राय द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया। जिसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया।
- ☞ वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान भी तैयार किया गया।
- ☞ के.सी. नियोगी ने सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था ली।
- ☞ इस नियोजन को इन्होंने समवर्ती सूची में रख दिया।
- ☞ और इन्हीं के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया।

योजना आयोग (Planning Commission)

- ☞ नियोजन के लिए 15 March, 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया जो रूस के संविधान से लिया गया। योजना आयोग को 1 Jan, 2015 को निति (National Institution for transforming India-NITI) आयोग कर दिया गया।
- **मुख्य कार्य**— पंचवर्षीय योजना बनाना।
- ☞ अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है।
- ☞ प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे।
- ☞ योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे।

राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)

- ☞ इसकी स्थापना 6 August, 1952 को हुई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं एवं केंद्रीय मंत्री परिषद् के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य रहते हैं। यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है।

Remark :- योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् दोनों की चर्चा संविधान में नहीं है, अतः यह गैर संविधानिक निकाय है। इन दोनों की रचना संविधान के बाद हुई। अतः इसे संविधानोत्तर निकाय कहते हैं।

Note :- योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं।

आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य—

1. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
2. सामाजिक न्याय।
3. पूर्ण रोजगार की प्राप्ति
4. गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन।
5. आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
6. निवेश एवं पूंजी निर्माण।
7. समान आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी।
8. आधुनिकीकरण
9. मानव संसाधन का विकास
10. निजीकरण उदारीकरण तथा वैश्वीकरण में गरीबों की सुरक्षा।
11. तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास।
12. धारणीय विकास।

नीति आयोग

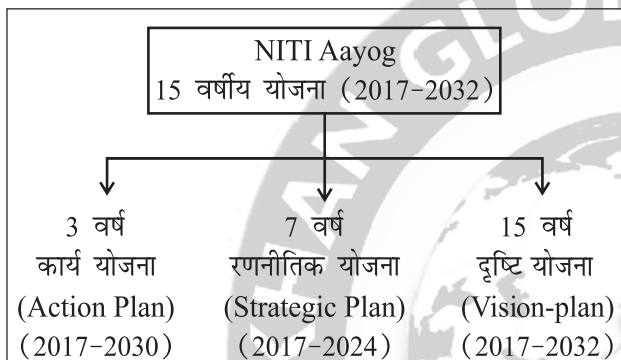
- ☞ राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान (नीति आयोग) की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी, 2015 को की गई।
- ☞ नीति आयोग भारत सरकार का थ्रिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक एवं तकनीकी सलाह देता है।

➤ नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य

- ☞ आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना।
- ☞ दीर्घकालिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का रूपरेखा तैयार करना।
- ☞ राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास हेतु रणनीतियों को विकसित करना।
- ☞ सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।

नीति आयोग की संरचना

- **अध्यक्ष**— भारत के पदेन प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी)
- **उपाध्यक्ष**— प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। (सुमन कुमार बेरी)
- **कार्यकारी परिषद**— सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघशासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल।
- **पूर्णकालीन सदस्य**— डॉ. अरविंद बिरमानी, वी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र तथा वी.के. पॉल।
- **पदेन सदस्य**— राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री), अमित शाह (गृह मंत्री), निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री)।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**— बी.वी. आर सुब्रमण्यम्।



योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर

योजना आयोग	नीति आयोग
यह एक पुरानी संस्था थी।	यह नई एवं आधुनिक संस्था है
गैर- सांविधिक और असंवैधानिक	गैर- सांविधिक और असंवैधानिक
सचिव	CEO
मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) नहीं होते हैं।	मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) होते हैं।
यह मंत्रालयों एवं राज्य सरकारी कोषों की वितरण करती थी।	कोषों का वितरण नहीं करती है।
Deputy chairman	Vice-chairman
Top-down approach	Bottom-up approach. (सहकारिता संघीय)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

- ☛ यह हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दोगुना बढ़ गया।

- ☛ प्रथम योजना में ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई।

अन्य प्रमुख उद्देश्य—

- ☛ कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- ☛ देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना।
- ☛ न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
- ☛ लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना।

Note:— योजना के अंतिम दो वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961)

- ☛ यह P.C. महानलोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग को स्थापित करना था।

Note :- भारी उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण इस योजना को असफल माना जाता है।

- ☛ भारत के बड़े-बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे हैं।
- ☛ इस योजना में राउरकेला (उड़ीसा) जर्मनी के सहयोग से, भिलाई (छत्तीसगढ़) सोवियत संघ के सहयोग से तथा दुर्गापुर (पं. बंगाल) U.K. के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई।

अन्य प्रमुख उद्देश्य—

- ☛ आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण करना।
- ☛ रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार।
- ☛ आय और धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना।
- ☛ झारखण्ड का बोकारो स्टील प्लांट USSR के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

- ☛ यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः सफूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई।
- ☛ इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ाना था।
- ☛ खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
- ☛ बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- ☛ देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि।

इस योजना की असफलता के तीन कारण हैं—

- (i) 1962 ई. में चीन से युद्ध जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई।
- (ii) 1965 ई. में पाकिस्तान से युद्ध
- (iii) 1966 का भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया— जय जवान-जय किसान।

Note :- यह अबतक की सबसे असफल योजना रही है।

- ☞ इस योजना के बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं बनी जिसे योजना अवकाश कहते हैं।

योजना अवकाश (Plan Holidays)

- ☞ वर्ष 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही तीन वार्षिक योजनाएं बनायी गई।
- ☞ वर्ष 1965 में भारत-पाक युद्ध, लगातार दो वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई।

➤ हरित क्रांति

- ☞ यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 ई. में प्रारंभ हुई।
- ☞ विश्व में इसका जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलंग को मानते हैं।
- ☞ भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामी नाथन हैं। हरितक्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था।
- ☞ हरित क्रांति में उन्नत बीज High yield variety के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
- ☞ हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूँ का उत्पादन बढ़ गया, जबकि धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन वहीं दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया।
- ☞ हरित क्रांति का केन्द्र UP के शामली में था तथा इससे सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ।

➤ द्वितीय हरित क्रांति

- ☞ इसमें अनुवांशिक रूप से वृद्धि किये गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटेकिली मोडीफाई (G.M.) फसल कहते हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

- ☞ इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी. आरगाडगिल ने तैयार किया है। मई, 1970 ई. में संसद में रखा।
- ☞ इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई क्योंकि, इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गई।
- ☞ इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
- ☞ परिवार नियोजन इस योजना का मुख्य लक्ष्यों में से एक था।
- ☞ ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना के समय में प्रारंभ की गयी थी।

अन्य प्रमुख उद्देश्य—

- ☞ राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि।
- ☞ आय एवं सम्पत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी करना।
- ☞ संतुलित विकास पर जोर देना।
- ☞ तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योग पर विशेष बल।

Note :- उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गए, 1971 ई. में बंगलादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया। जिस कारण यह योजना असफल हो गई।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78)

- ☞ इस योजना में पहली बार 'गरीबी हटाओ' का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया।
- ☞ इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य 'गरीब हटाओ' तथा 'आत्मनिर्भरता की प्राप्ति' थी।
- ☞ गरीबी हटाने के लिए वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया तथा इसी वर्ष 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई।
- ☞ 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' इसी योजना में प्रारंभ की गई।
- ☞ इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया और इसके स्थान पर अनवरत योजना लाया गया।
- ☞ इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा न्यायपूर्ण श्रम शक्ति के विकास को महत्व दिया गया।
- **अनवरत योजना [Rolling Plan (1978-80)]**
- ☞ अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक "एशियन ड्रामा" में किया था, जिसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया।
- ☞ यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को DDT लकड़ावाला ने तैयार किया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

- ☞ इस योजना में औद्योगीकरण के साथ-साथ गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया।
- ☞ जनता पार्टी की सरकार द्वारा पांचवी योजना को समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर छठी योजना (1978-83) लायी परंतु इस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी पुनः (1980 में) सत्ता में आई तो छठी योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक के लिए लागू किया।
- ☞ इसी दौरान 'मानक व्यक्ति वर्ष' को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया।
- ☞ यह योजना अगत-निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना में एक कार्यदल ने 'गरीबी निर्देशांक' तैयार किया तथा गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया।

- छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई।
- अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना में अपनाया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

- इसे डॉ. चक्रवर्ति ने तैयार किया। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया।
- यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी।
- इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया।

Note :- यह एक सफल योजना रही।

अन्य प्रमुख उद्देश्य-

- खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास।
- **योजना अवकाश (1990-1992)**
- इस समय राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। जिसमें अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

- यह योजना दो वर्ष की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट था।
- इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया।
- इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा तथा उदारीकरण पर जोर दिया गया। जिस कारण इसे शिक्षा में समर्पित योजना कहते हैं।
- यह योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत 'जॉन डबल्यू मुलर' मॉडल पर आधारित थी।

अन्य प्रमुख उद्देश्य-

- शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना।
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास।
- पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का विकास।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

- यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी इसमें न्याय पूर्ण वितरण प्रणाली को अपनाया गया।
- 'सामाजिक न्याय का समता' के साथ आर्थिक विकास नौवीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था।
- इस योजना का लक्ष्य राजकोषीय नीति लागू करना था ताकि केन्द्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्व घाटे को कम किया जा सके।

Note:- यह योजना भूकम्प, कारगिल युद्ध तथा 1996 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

- अधिक व्यापक आगत-निर्गत मॉडल पर आधारित दसवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007) ऐसे समय लागू की गई जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर अपनी चरम पर था।
- इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया।
- इस योजना में कृषि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है।
- इस योजना में उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करने वाले थे।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

- इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए सामावेशी विकास चलाया गया।
- इस योजना में तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया।
- इसी योजना के दौरान 1 अप्रैल, 2010 को मिड-डे-मिल योजना प्रारंभ की गई हालांकि इस योजना को संसद ने 2005 में मंजूरी दी थी।
- इस योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया किंतु वन 24% से घट कर 22% रह गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

- इसमें प्रशासनिक सुधार तथा भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया किंतु यह दोनों बढ़ गया। इस योजना में परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया।
- तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास इस योजना का उपशीर्षक है।
- यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट का सामना कर रही थी जो 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में यूरोपीय जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा।
- इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तीव्र किया जाए और साथ में यह भी सुनिश्चित हो कि हमारी विकास प्रक्रियाएं समावेशी एवं धारणीय रहे।

□□□

- ☞ किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के व्यौरे को बजट कहते हैं।
 - ☞ बजट फ्रेंच भाषा के बुजेट (Bougeut) शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है **चमड़ा का थैला**।
 - ☞ 1773 ई० में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री राबर्ट वालपोल ने पार्लियामेंट में वित्तीय प्रस्ताव पेश करने हेतु एक चमड़े के थैला खोलकर उससे संबंधित कागजात निकाला तो संसद सदस्यों ने मजाक में इसे जादू के थैले के अर्थ में बजट खुल गया, बजट खुल गया कहा। इसके बाद वार्षिक आय-व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा।
 - ☞ भारत का पहला बजट लार्ड कैनिंग के समय 7 अप्रैल, 1860 को तत्कालीन वित्तमंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कहा जाता है।
 - ☞ स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर, 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. सन्मुखम् सेट्टी द्वारा पेश किया गया था।
 - ☞ गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 जॉन मेथाई ने पेश किया।
- भारत के तीन प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किए—**
1. जवाहरलाल नेहरू
 2. इंदिरा गांधी
 3. राजीव गांधी।
- ☞ भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, जबकि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।
 - ☞ सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। इन्होंने 10 बार (8 बार नियमित, 2 बार अंतरिम) बजट प्रस्तुत किए।
 - ☞ प्रारम्भ में रेल बजट एवं आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था लेकिन 1924 ई० में एकवर्ध समिति के सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया तथा 2016 में पुनः रेल बजट एवं आम बजट को मिला दिया गया।
 - ☞ भारत में बजट प्रस्तुत 2017 से 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है।
 - ☞ बजट को तैयार कराने का काम प्राक्कलन समिति करती है।
 - ☞ बजट का टीवी पर प्रसारण 1992 से प्रारम्भ हुआ।
 - ☞ बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है किन्तु वे वित्तमंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं।
 - ☞ बजट प्रस्तुत करने की चर्चा संविधान में नहीं है बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। एक वर्ष के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण [Annual Financial Statement (AFS)] कहा जाता है।
 - **अनु० 112**
 - ☞ इसमें बजट के तहत वित्तमंत्री भिन्न-भिन्न कार्य के योजना को प्रस्तुत करते हैं।
 - **अनु० 113**
 - ☞ इनमें प्राक्कलन के तहत खर्च का विवरण दिया जाता है।
 - **अनु० 114**
 - ☞ विनियोग विधायक के तहत धन निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है। जबतक विनियोग विधायक पारित नहीं हो जाता है तबतक संसद से धन नहीं निकाला जा सकता है। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय धन (कोष) का रक्षक कहते हैं।
 - **अनु० 115**
 - ☞ इसमें अतिरिक्त अनुदान के तहत प्राक्कलन द्वारा दिए गए पैसे घट जाने पर पैसा निकाला जाता है।
 - **अनु० 116**
 - ☞ इसमें लेखानुदान के द्वारा अग्रिम राशि निकाल ली जाती है।

बजट के प्रकार

1. शून्य आधारित बजट

- ☞ जब बजट में पिछला लेन-देन को छोड़कर एकदम नए सिरे से बजट बनाया जाता है तो उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं।
- ☞ भारत में शून्य आधारित बजट 1987-88 ई. में राजीव गांधी ने लाया तथा विश्व में शून्य आधारित का प्रथम प्रयोग 1977 ई. में अमेरिका के जिमी कार्टर ने किया।
- ☞ शून्य आधारित बजट के जनक अमेरिका के पितर फायर थे। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश में अपनाया गया।

2. जेन्डर बजट

- ☞ जिस बजट में स्त्री पुरुष के लिए अलग से कुछ प्रावधान हो जेन्डर बजट कहलाता है।
- ☞ 2001 में महिला शक्तिकरण के बाद जेन्डर बजट को अधिक बढ़ावा दिया गया।
- ☞ इसका सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था।

3. संतुलित बजट

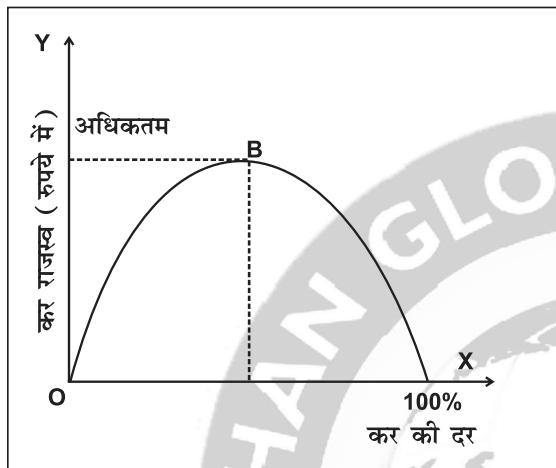
- ☞ वैसे बजट जिसमें आय तथा व्यय बराबर हो संतुलित बजट कहलाता है।

4. आउट कम बजट

- जब सरकार पैसा को खर्च करती है उस धन द्वारा किए गए कार्य का रिपोर्ट कार्ड (प्रगति) को आउटकम बजट कहते हैं।
- इस बजट की शुरुआत श्री पी.चिदम्बरम ने 2005 ई. में किया।

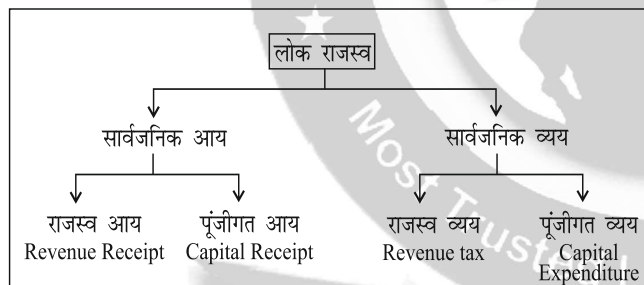
➤ लैफर वक्र (Laffer Curve)

- इसका प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री ऑथर लैफर द्वारा किया गया जो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को दर्शाता है।



लोक राजस्व (Public Finance)

- सरकारी लेनदेन को लोक राजस्व कहते हैं।



➤ सार्वजनिक आय (Public Revenue)

- सरकार के कुल आय को सार्वजनिक आय कहते हैं।

यह दो प्रकार का होता है—

1. राजस्व आय

- वैसा आय जिसे सरकार लौटाती नहीं है, राजस्व आय कहलाता है अर्थात् इसपर सरकार की देनदारी (ऋणभार) शून्य रहता है।
- केन्द्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है जबकि राज्य सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर है।

2. पूंजीगत आय

- सरकार का वैसा धन जिसे सरकार को लौटाना पड़े अर्थात् जिसपर सरकार की देनदारी रहती है।

Ex. :- बैंक तथा बॉन्डपेपर के रूप में जमा धन।

Remark :- सरकार अपने पूंजीगत आय को बनाए रखने के लिए cashless पर विशेष जोर दे रही है।

➤ सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

- सरकार के कुल व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं।

यह दो प्रकार का होता है—

1. पूंजीगत व्यय

- यह एक वर्ष में प्रारम्भ होकर कई वर्षों तक धीरे-धीरे होता रहता है यह बहुत बड़ा व्यय होता है इसके द्वारा ढाँचागत विकास होता है।

Ex. :- सड़क, पुल, Airport।

2. राजस्व व्यय

- यह व्यय अल्पकालीन तथा छोटा होता है, जिस वर्ष यह प्रारम्भ होता है उसी वर्ष समाप्त हो जाता है।

Ex. :- सहायता राशि, सब्सिडी, etc.

➤ घाटा (Deficite)

- जब व्यय आय से अधिक हो जाए तो उसे घाटा कहते हैं। घाटा कई प्रकार का होता है।

1. राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व आय

2. पूंजीगत घाटा = पूंजीगत व्यय – पूंजीगत आय

3. सार्वजनिक घाटा = सार्वजनिक व्यय – सार्वजनिक आय

सार्वजनिक घाटा = पूंजीगत घाटा + राजस्व घाटा

Note :- सार्वजनिक घाटा को बजट घाटा कहते हैं।

➤ राजकोष घाटा (Fiscal Deficite)

- जब बजट घाटा में ऋणभार को जोड़ देते हैं तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।

Note :- राजकोषीय घाटा सबसे प्रमुख घाटा है। जिस देश का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, उस देश की प्रगति में उतनी अधिक बाधा आएगी।

➤ प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

- राजकोषीय घाटा में ब्याज घटाने पर प्राप्त घाटा को प्राथमिक घाटा कहते हैं।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

राजकोषीय घाटा = प्राथमिक घाटा + ब्याज भुगतान

➤ मौद्रिक घाटा (Monetary Deficit)

- नए नोट को छपने पर आए खर्च करने के कारण लगने वाला घाटा, मौद्रिक घाटा कहलाता है। यह तभी होगा जब सरकार अत्यधिक नोट छापे या नोट बदल दें।

➤ योजनागत व्यय

- वैसा व्यय जिसका अनुमान पहले से ही लगाया जा चुके हो उसे योजनागत व्यय कहते हैं।

Ex. :- वेतन, विकासात्मक परियोजनाएं।

➤ गैर योजनागत व्यय

- वैसा व्यय जिसका पूर्व अनुमान सरकार को न हो, गैर योजनागत व्यय कहलाता है।

Ex. :- सहायता राशि, सब्सिडी, रक्षा व्यय।

- यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसे कानूनी रूप से देना ही पड़ता है। कर उतना ही निश्चित है जितना की मृत्यु क्योंकि यह सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। कराधान का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था।

- यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- इसकी निगरानी के लिए PAN CARD (Permanent Account Number) दिया जाता है।

वर्तमान (Financial Year 2024) में Income Tax के 6 Slab है-

Tax के प्रकार

1. प्रगतिशील कर (Progressive Tax)

- यह आय के बढ़ने से बढ़ता जाता है और इसका प्रभाव अमीर पर ज्यादा पड़ता है। यह आय एवं सम्पत्ति के असमानता को दूर करता है।

2. प्रतिगामी कर (Regressive Tax)

- यह कम आय वालों पर अधिक Tax लगता है। यह गरीबों को अधिक प्रभावित करता है।

3. समानुपाती (Proportional)

- वैसा कर जो आय के घटने या बढ़ने से बदलता नहीं है समानुपाती कर कहलाता है। यह गरीब तथा अमीर को समान रूप से प्रभावित करता है।

4. अधोगामी कर (Degressive Tax)

- यह कर आय के बढ़ने से प्रारम्भ में बढ़ता है। किंतु एक निश्चित सीमा पर जाकर एक समान हो जाता है। इसमें प्रारंभ में प्रगतिशील के गुण होते हैं। बाद में समानुपाती के गुण होते हैं।
- इसमें सरकार बिना कुछ दिए धन ले लेती है।

➤ शुल्क (Fee)

- इसमें सरकार कुछ देने के बाद धन लेती है।

➤ करापात (Incidence of Tax)

- जिस व्यक्ति पर tax लगाया जाता है, उसे करापात कहते हैं।

➤ कराघात (Impact of Tax)

- जो व्यक्ति Tax की धन राशि देता है। उसे कराघात कहते हैं।

Income Tax Slab	
0 – 3 लाख	No Tax
3 – 6 लाख	5%
6 – 9 लाख	10%
9 – 12 लाख	15%
12 – 15 लाख	20%
15 लाख ↑	30%

- Income का ब्योरा देने के लिए कम्प्यूटेशन बनना पड़ता है। कम्प्यूटेशन (Computation) के इनकम के आधार पर ही Income Tax ITR जमा करना होता है।

➤ उपकर (Cess)

- Tax के अतिरिक्त लगाया गया कर शेष कहलाता है। शेष की धनराशि के द्वारा सरकार प्रौढ़ शिक्षा सफाई, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि पर खर्च करती है।
- यह Tax के अतिरिक्त अलग से Tax लिया जाता है। जिसे Tax On Tax कहते हैं। इसे 4% तक लिया जाता है। Cess का पूरा पैसा केन्द्र सरकार के पास रहता है।

➤ अधिभार (Sur Charge)

- यह भी Tax पर ही लिया जाता है। इसे भी Tax On Tax कहते हैं। यह तब लिया जाता है जब कोई व्यक्ति 50 लाख से अधिक देता है। यह 10% तक लिया जाता है।

➤ संपत्ति कर (Wealth Tax)

- संपत्ति से अर्जित किए गए लाभ पर लगने वाले कर को संपत्ति कर कहते हैं।
- यह राज्य सरकार का कर है।

➤ निगम कर (Corporate Tax)

- यह बड़े-बड़े कम्पनी पर लगाया जाता है। यह प्रत्यक्ष कर है। यह मुनाफे के 30% पर लगाया जाता है। केन्द्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है।

Ex. :- Tata, बिरला, Reliance

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

- वैसा कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अन्ततः उसी से वसूल भी किया जाता है, Direct Tax कहलाता है।
- Ex. :-** आयकर, सम्पत्ति कर, निगम कर, उपहार कर, धन कर, कृषि कर आदि।

➤ आयकर (Income Tax)

- यह कर सीधे करदाता की भुगतान करने की क्षमता से संबंधित होता है। जिसे प्रत्येक वर्ष करदाता को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा केन्द्र सरकार को आयकर के रूप में देना होता है।

➤ उपहार कर (Gift Tax)

- यह प्रत्यक्ष कर है। जब 50 हजार से अधिक का Gift मिलता है, तो यह Tax लगाया जाता है। यह 30% होता है।

Ex. :- K.B.C. में विजेता को 5 करोड़ में 3.5 करोड़ रुपये मिलते हैं।

Note :- विवाह में समधी द्वारा दिए गए उपहार पर यह Tax नहीं लगता है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

- यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता बल्कि दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान करता है। यह वस्तुओं पर लगाया जाता है। जैसे बिक्री कर, सीमा शुल्क, वाहन कर।

➤ सीमा शुल्क (Custom Duty)

- यह कर देश के सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आनेवाली वस्तुओं पर लगता है।
- इस कर को केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है जबकि वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र एवं राज्य के बीच बांटा जाता है।

➤ उत्पाद शुल्क (Excise Duty)

- यह कर केंद्र सरकार द्वारा किसी देश के भीतर वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है।
- मादक पेय पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू, गांजा आदि पर राज्य सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क लगाया जाता है किंतु तंबाकू से निर्मित वस्तु जैसे सिगरेट पर केंद्र सरकार कर लगाती है।
- स्थानीय सरकार के कारण इसे पंचायत एवं नगरपालिका के लोग लेते हैं।

Ex. :- मालगुजारी, भवन कर, खेती कर, चुंगीकर।

➤ VAT (Value Added Tax)

- इसको सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था। भारत में इसे L.K. झा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। यह अप्रत्यक्ष कर है। इसे बिक्री पर राज्य सरकार लेती थी।

Note :- (Central Value Added Tax (CENVET) केंद्र सरकार उत्पादन पर लेती थी। Cenvet अप्रत्यक्ष कर था। Vet Tax को सबसे पहले 2005 में हरियाणा ने माना था जबकि सबसे अंत 2008 U.P. ने माना।

➤ सेवाकर (Service Tax)

- यह राज्य सरकार लेती थी। इसे 1994-95 में लाया गया।

Note :- वर्तमान में Vat तथा Service Tax को समाप्त करके GST लाया गया है।

- वर्ष 2003 में 88वां संविधान संशोधन द्वारा इस कर को केंद्र सूची में डाल दिया गया।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) (Goods and Service Tax)

- यह एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत का GST कनाडा मॉडल पर आधारित है। विश्व में सबसे ज्यादा GST की दर भारत में है। GST चोरी करने वाले को 5 साल जेल का प्रावधान होगा।
- GST पंजीकरण करने पर 15 अक्षर का पंजीकरण नम्बर दिया जाता है।

GST – Identification Number

10 –	<u>PYKAZ6318K</u>	<u>IPQ</u>
State	PAN No.	Business

- GST के दायरे में 20 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी को रखा गया है।
- GST के सभी निर्णय GST परिषद् लेती है।
- GST परिषद् में 33 सदस्य होते हैं।

- वित्तमंत्री = 1 अध्यक्ष
- राज्यमंत्री = 1
- राज्य के वित्तमंत्री = 28
- UT के वित्तमंत्री (दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मूकश्मीर) = 3

Note :- GST परिषद् के अध्यक्ष वित्तमंत्री होते हैं। भारत में GST अरविन्द समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। GST लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया।

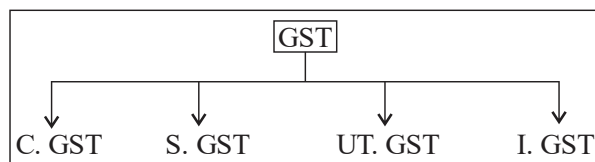
- GST की चर्चा अनु. 379 में है।
- IGST की चर्चा अनु. 369 में है।
- भारत की GST VAT को हटाकर लाया गया है।
- भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है।
- GST लागू करने वाले पहला राज्य असम था।
- GST आने से सेवा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया।

- GST Monthly भरा जाता है।
- GST प्रत्येक महीना के 24 तारीख को भर देना होता है।

भारत में GST के चार Class बनाये गये हैं-

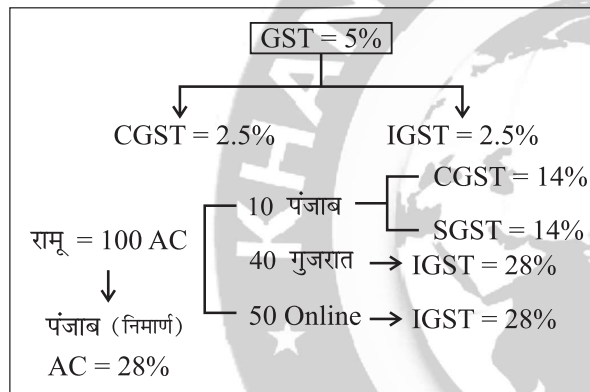
- 5% – इसमें आवश्यक वस्तु को रखा गया है।
- 12 % – इसमें उपयोगी वस्तु को रखा गया है।
- 18% – इसमें आरामदायक वस्तु को रखा गया है।
- 28% – इसमें विलास्तापूर्ण वस्तुओं को रखा गया है।

GST को चार श्रेणी में बाँटा गया है-



- **Central GST (C.GST)**
 - ☞ यह केन्द्र सरकार लेती है यह वस्तु के उत्पादन पर लगता है।
- **State GST (S.GST)**
 - ☞ जिस राज्य में वस्तु बनी है, यदि उसी राज्य में बेची जाय तो SGST लगता है।
- **Union Territory GST (UT.GST)**
 - ☞ यह केन्द्रशासित प्रदेश में बनी वस्तु केन्द्रशासित प्रदेश में ही बिकती है। उसे UT. GST कहते हैं।
- **Integrated GST (I.GST)**
 - ☞ यदि किसी राज्य में बनी वस्तु दूसरे राज्य में बेची जाती है जिस राज्य में उसे बेचा जाता है। वह राज्य IGST लेता है।
 - ☞ Online की सभी खरीदारी IGST के अंतर्गत आता है।

Note :- चार प्रकार के GST में से C.GST अनिवार्य रूप से देना ही है। शेष तीन GST में से कोई एक GST लगेगा।



महत्वपूर्ण कर सुधार समिति

समितियां	कार्य क्षेत्र
राजा चेलैया समिति	कर सुधार
वाँचू समिति	प्रत्यक्ष कर
केलकर समिति	प्रत्यक्ष कर
एल.के. झा समिति	अप्रत्यक्ष कर
रेखा समिति	अप्रत्यक्ष कर
भुरेलाल समिति	मोटरवाहन में कर वृद्धि
रंगराजन समिति	पेट्रोलियम उत्पाद पर कर
वाई.वी. रेड्डी	आयकर में छूट

प्रत्यक्षकर (Direct Tax)	अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
सम्पत्ति कर (Assets Tax)	उत्पादन कर (Excise Tax)
कृषि कर (Agriculture Tax)	सेवा कर (Service Tax)
धन कर (Wealth Tax)	सीमा कर (Custom Tax)
आय कर (Income Tax)	बाजार कर (Market Tax)
निगम कर (Corporate Tax)	बिक्री कर (Sales Tax)
व्यवसाय कर (Business Tax)	मनोरंजन कर (Entertainment Tax)
भू-राजस्व कर (Land Revenue Tax)	प्रोफेशनल कर (Professional Tax)
मृत्यु कर (Death Tax)	टोल कर (Toll Tax)
उपहार कर (Gift Tax)	स्टाम्प कर (Stamp Tax)

विभिन्न सरकार द्वारा लगाए गए प्रमुख कर

केन्द्रीय कर (Central Tax)	राज्य कर (State Tax)	स्थानीय कर (Local Tax)
सीमा शुल्क (Custom Duty)	कृषि कर (Agriculture Tax)	गृह कर (House Tax)
आय कर (Income Tax)	राजस्व कर (Land Revenue)	चुंगी कर (Toll Tax)
सेवा कर (Service Tax)	स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty)	कृषि भूमि पर कर
केन्द्रीय उत्पाद कर (Central Excise Duty)	राज्य उत्पाद कर (State Excise Duty)	गाँव के हाट / मेला पर कर (मनोरंजन कर)

□□□

08.

व्यापार संतुलन (Trade Balance)

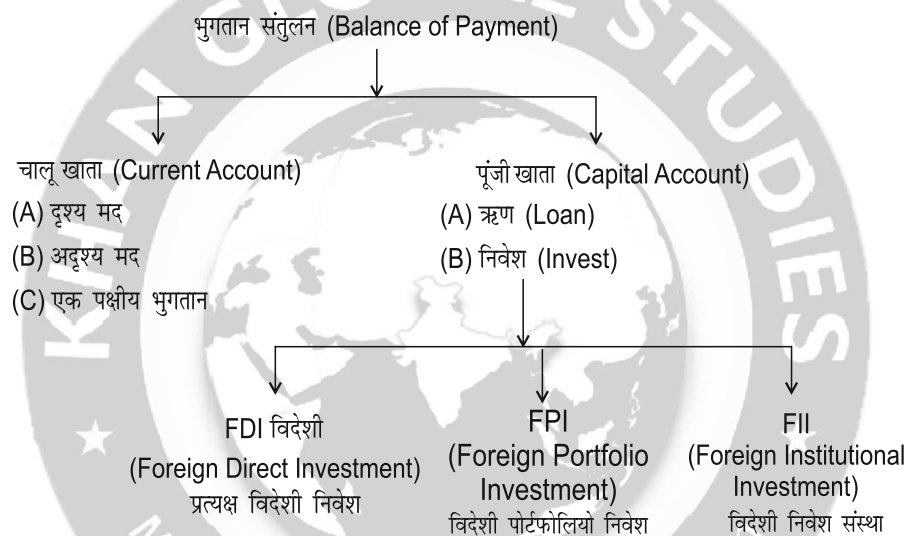
☞ कई देशों के बीच जब व्यापार होता है, तो आयात-निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि यह धनात्मक है तो देश के लिए अच्छा होता है।

Q. भारत चीन को 18 अरब डॉलर (वार्षिक) का निर्यात करता है। जब कि चीन से 72 अरब डॉलर का आयात करता है। तो भारत का व्यापार संतुलन ज्ञात करें।

निर्यात – आयात

$18 - 72 = 54$ अरब डॉलर (ऋणात्मक व्यापार संतुलन)

भुगतान संतुलन (Balance of Payment)



चालू खाता (Current Account)

☞ यह दृश्यमान (दृश्य मद) और अदृश्यमान (अदृश्यमद) वस्तुओं के आयात-निर्यात को दर्शाता है।

- A. **दृश्यमद (Visual Item):**— इसमें सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं (Goods) का आयात एवं निर्यात सम्मिलित होता है।
- B. **अदृश्य मद (Invisible Item) :**— इसमें विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं (Services) शामिल होते हैं।
- C. **एक पक्षीय भुगतान :-** इसमें किसी स्रोत से प्राप्त अनुदान व उपहार (Gift) को शामिल किया जाता है।

का कोई भी Branch लगाती है तो उसे FDI कहते हैं।

➤ **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI (Foreign Portfolio Investment)**

☞ जब कोई विदेशी कम्पनी भारत में 10% से कम निवेश करती है तो उसे FPI कहते हैं।

➤ **विदेशी निवेश संस्था FII (Foreign Institutional Investment)**

☞ वैसी संस्था तथा Bank जो FDI तथा FPI में मदद करते हैं उसे FII कहते हैं।

पूंजी खाता (Capital Account)

☞ यह मुख्य रूप से किसी देश द्वारा एक वर्ष के दौरान विदेशी संपत्तियों और देनदारियों के व्यापार से संबंधित है।

☞ विदेशी निवेश तथा ऋण इसके मुख्य घटक हैं।

➤ **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI (Foreign Direct Investment)**

☞ जब कोई विदेशी कम्पनी या संस्था भारत में किसी कम्पनी की 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है और अपने कम्पनी

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया RBI (RESERVE BANK OF INDIA)

☞ इसका गठन 1934 में गठित समिति हिल्टन यंग के सिफारिश पर 1 April, 1935 को किया गया। हिल्टन यंग आयोग ने इसे केन्द्रीय बैंक का दर्जा दिया। इसके पहले अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ थे तथा इसके पहले भारतीय अध्यक्ष C.D देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।

- ☞ RBI की स्थापना 100, 100 के 5 लाख शेयर को मिलाकर हुई थी किन्तु 1 January, 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया।

इसका मुख्यालय मुम्बई है जबकि चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं—
Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkatta.

- ☞ इसका विदेश में कार्यालय लंदन में है। RBI प्रत्येक राज्य के वित्तीय लेनदेन को देखती है। किन्तु जम्मूकश्मीर के लेनदेन को SBI देखती है।

- ☞ RBI का लेखा वर्ष 1 July से 30 जून तक होता है। RBI के कार्यों का संचालन 21 सदस्यों वाले बोर्ड सदस्य द्वारा होता है।

1 = गवर्नर

4 = Deputy गवर्नर

4 = क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर (अध्यक्ष)

2 = वित्त मंत्रालय के अधिकारी

10 = अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार

➤ **RBI के कार्य**

- सरकारी बैंक के रूप में कार्य।
- अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना।
- आर्थिक आकरे जारी करना।
- मुद्रा का विनिमय (Exchange)
- बैंकों पर नियंत्रण रखना।
- साख नियंत्रण
- नोट का निर्गमन
- विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण

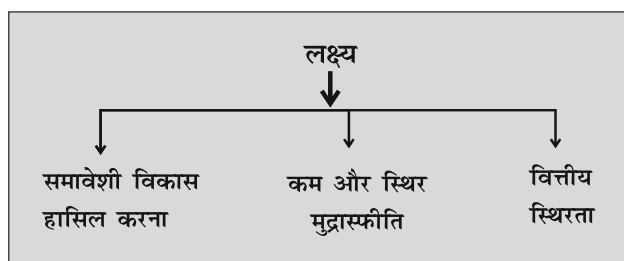
➤ **साख नियंत्रण (Credit Control)**

- ☞ बाजार की तरलता को नियंत्रित करना साख नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए RBI मौद्रिक नीति को अपनाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत M.S.F, Reporate, Bank Rate, CRR, SLR, खुले बाजार की नीति (प्रतिभूति की बिक्री) आदि आते हैं।
- ☞ RBI का कार्य साख सृजन करना नहीं होता है बल्कि साख नियंत्रण होता है।
- ☞ साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं।

➤ **मौद्रिक नीति (Monetary Policy)**

- ☞ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाले नीतियां को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है।
- ☞ इसका संचालन केंद्रीय बैंक अर्थात् RBI करता है।
- ☞ इस नीति की घोषणा एक वित्तीय वर्ष में 2014 के बाद 6 बार अर्थात् द्विमासिक की जाती है।

➤ **मौद्रिक नीति के लक्ष्य**



➤ **बैंक दर (Bank Rate)**

- ☞ RBI Bank को 14 दिन से अधिक के लिए (दीर्घकालिक) जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे Bank Rate कहते हैं।
MSF > Reporate > Bank rate

- ☞ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। जबकि मुद्रा अवस्फीति का सामना करने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है।

➤ **रेपो दर (Repo Rate)**

- ☞ RBI बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए जिस दर पर ऋण देती है उसे Repo Rate कहते हैं। यह लगभग 4% तक है।

- ☞ इसका प्रयोग RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है।

➤ **सीमांत स्थायी सुविधा [MSF (Marginal Standing Facility)]**

- ☞ RBI बैंकों को एक दिन के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे MSF कहते हैं।

➤ **रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)**

- ☞ जब बैंक अपना अतिरिक्त धन RBI के पास रखते हैं, तो RBI द्वारा दिया गया ब्याज दर Reverse Reporate कहलाता है।

➤ **नगद आरक्षित अनुपात CRR (Cash Reserve Ratio)**

- ☞ बैंकों को अपने कुल जमा का 4% RBI के पास रखना होता है। जिस पर RBI कोई भी ब्याज नहीं देती है। इसे ही नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं।

- ☞ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है।

- ☞ अत्यधिक मुद्रा स्फीति के समय RBI नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ा देता है।

➤ **वैधानिक तरलता अनुपात SLR (Statutory liquidity Ratio)**

- ☞ बैंक को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है जिसे SLR कहते हैं।

➤ **PLR (Prime Lending Rate)**

- ☞ बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देती है उसे PLR कहते हैं।

➤ **Base Rate**

- ☞ बैंक अपने चुनिंदा ग्राहक को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देती है। Base Rate कहते हैं।

➤ **तरलता (Liquidity)**

- ☞ नगद पैसा को तरलता कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक होता है।

➤ **मुद्रास्फीति (Inflation)**

- ☞ तरलता के बढ़ जाने से मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। जिससे महंगाई बढ़ जाती है।

$$\text{तरलता} \propto \text{स्फीति} \propto \text{महंगाई}$$

$$\text{Repo, CRR, SLR} \propto \frac{1}{\text{तरलता}}$$

➤ **NEER (Normalise effective exchange rate)**

- इसका निर्धारण IMF करती है।
- इसके द्वारा एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से तुलना किया जाता है। Dollar का NEER 75 भारतीय रुपया होता है। NEER का संबंध बैंकिंग से नहीं है।

➤ **खुले बाजार की नीति**

- प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री खुले बाजार की नीति कहलाती है। यह मौद्रिक नीति का ही हिस्सा है। इसके अंतर्गत Bond Paper, LIC आदि को रखते हैं। जब सरकार प्रतिभूतियों को बेचती है तो तरलता घट जाती है।
- कालाधन के अधिकता से मौद्रिक नीतियाँ अधिक प्रभावित हो पाती है। इसी कारण मोदीजी ने नोट बदल दिया।
- कालाधन को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं।

मुद्रा-स्फीति (Inflation)

- मुद्रा का अत्यधिक बढ़ जाना मुद्रा स्फीति कहलाता है। मुद्रा स्फीति के कारण महंगाई बढ़ जाती है। और मुद्रा का मूल्य (Value) घट जाता है।

वस्तु की मांग ↑ + वस्तु की आपूर्ति ↓ ⇒ वस्तु की कीमत ↑
(मुद्रास्फीति)

तरलता के आधार पर मुद्रा स्फीति को चार भाग में बाँटते हैं—

- रेंगती मुद्रा स्फीति
- चलती मुद्रा स्फीति
- दौड़ती मुद्रा स्फीति
- अति मुद्रा स्फीति

मुद्रा स्फीति (महंगाई) के उत्पत्ति के तीन कारण है—

(i) तरलता में वृद्धि

Eg :- वेनेजुएला

(ii) लगातार प्रेरित मुद्रा स्फीति

- इसमें लागत बढ़ जाता है, जिस कारण महंगाई बढ़ जाती है।

Eg :- कोयला का रेट बढ़ना, चाय का महंगा होना।

Note :- लगातार प्रेरित मुद्रा अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि यह स्थाई रहती है। मुद्रा स्फीति में मुद्रा बढ़ जाता है जिस कारण कार्य शक्ति, मांग तथा महंगाई तीनों बढ़ जाता है, किन्तु मुद्रा का मूल्य घट जाता है। जिस कारण रोजगार पर लगा व्यक्ति भी बाजार कीमत पर रोजगार नहीं पा पाता है और बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाता है।

(iii) माँग प्रेरित मुद्रा स्फीति

- इसमें माँग के बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है।

Eg :- लगन में D.J, ईद में सेवई

➤ **मुद्रा स्फीति से लाभ**

- ऋण (देनदार), किसान, उद्योगपति व्यापारी, परिवर्तित आय वाला व्यक्ति, विक्रेता, निर्यातक

➤ **मुद्रा स्फीति से हानि**

- ऋणदाता (लेनदार), स्थिर आय वाला व्यक्ति, ग्राहक, आयतक
- मुद्रा स्फीति को रोकने के उपाय को अपस्फीति कहते हैं। इसे रोकने के लिए प्रतिभूति की बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ा देना चाहिए। तथा मौद्रिक नीति को कठोर कर देना चाहिए।

➤ **मंदी (Recession)**

- मंदी वह स्थिति है जिसमें तरलता अत्यधिक घट जाती है। जिस कारण व्यापार प्रभावित हो जाता है।
- अधिक देर तक मंदी रहने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

➤ **मंदीगत मुद्रास्फीति/निस्पंदन (Stagflation)**

- जब मंदी तथा मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो जाए तो उसे मंदीगत मुद्रास्फीति/निस्पंदन कहते हैं। इस स्थिति में पहले मंदी को ठीक करने के लिए तरलता बढ़ा देना चाहिए उसके बाद मुद्रा स्फीति को ठीक करना चाहिए।

➤ **धारणीय मुद्रास्फीति (Sustainable Inflation)**

- यह ऐसी मुद्रास्फीति दर है जिसमें अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर गतिमान रहती है।
- इस प्रकार के मुद्रास्फीति में आम लोगों को कोई विशेष समस्या नहीं होती है।

➤ **मुद्रास्फीति की गणना**

- भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल सूचकांक के आधार पर की जाती है।

- वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2011-12 का प्रयोग किया जाता है।

➤ **मुद्रास्फीति की सूचक**

● **थोक मूल सूचकांक (Wholesale Price Index)**

WPI – यह वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

● **उपभोक्ता मूल सूचकांक (Consumer Price Index) CPI**– यह प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाले

वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि की गणना करता है।

Note :- फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)– इसका प्रतिपादन न्यूजीलैण्ड अर्थशास्त्री A.W. Phillips द्वारा किया गया था। इसमें बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति की दर में संबंध को बताता है।

➤ नोट का निर्गमन

- ☛ 1 रु. के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं जब की उससे ऊपर के मूल्य के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है।
- ☛ नोट जारी करने के लिए RBI आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती थी जिसके तहत RBI को 400 करोड़ मूल्य रखना होता था। जिसमें 215 करोड़ मूल्य का भारतीय रुपया या सोना रखा जाता था, जबकि शेष 185 करोड़ मूल्य का विदेशी मुद्रा रखा जाता था।
- ☛ वर्तमान में RBI नोट छापने के लिए **न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली** को अपनाती है। इसके तहत RBI को 200 करोड़ रुपया रखने होते हैं। इसमें 115 करोड़ मूल्य का भारतीय रुपया, या सोना होता है। जबकि शेष 85 करोड़ मूल्य का विदेशी मुद्रा रखनी होती है।
- ☛ भारत में नोट छापने के चार प्रेस हैं। जिसमें देवास तथा नासिक के प्रेस केन्द्र सरकार के अधीन हैं। जबकि हैदराबाद तथा साहबानी के प्रेस RBI के अधीन हैं।

➤ देवास प्रिंटिंग प्रेस (मध्य प्रदेश)

- ☛ यह केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा नोट का प्रेस है। इसे बैंक नोट प्रेस कहते हैं। यहाँ 20, 50, 100 तथा 500 के नोट छापते हैं।

➤ नासिक प्रिंटिंग प्रेस

- ☛ इसे Currency नोट प्रेस कहते हैं। यहाँ 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के नोट छपते हैं। हैदराबाद तथा साहबानी के प्रेस सबसे आधुनिक हैं। इसमें सभी प्रकार के नोट छपते हैं।

➤ टकसाल (Mint)

- ☛ सिक्का बनाने वाले मशीन को टकसाल कहते हैं। भारत में 5 टकसाल है।

(i) मुम्बई (स्थापना - 1830, सबसे पुराना)

(ii) चेरापल्ली तमिलनाडु

(iii) हैदराबाद

(iv) कोलकाता

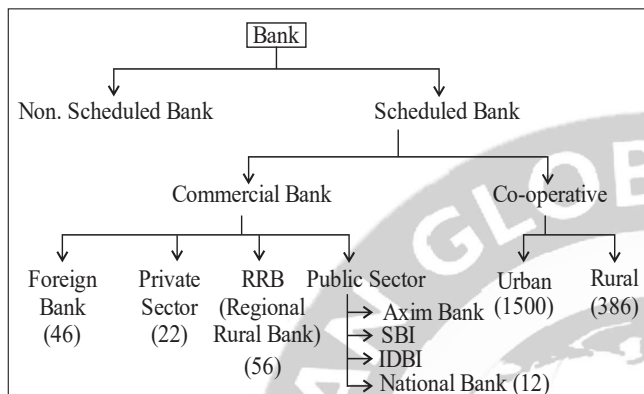
(v) नोएडा (स्थापना - 1989, सबसे आधुनिक)

Note :- कोलकाता- टकसाल में भारत रत्न तथा शेष पदक एवं तमगा बनता है।

□□□



बैंक (BANK)



➤ अनुसूचित बैंक

- वैसी बैंक जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख के बराबर हो।
- यह बैंक RBI से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करते हैं।

➤ वाणिज्यिक बैंक

- वैसी बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं अर्थात् विभिन्न प्रकार के खाते को खोलकर जनता से जमा राशी स्वीकार करते हैं एवं उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं उसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं।
- बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को वाणिज्यिक बैंक का जननी कहा जाता है।
- भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक Bank of Hindustan था। इसे अंग्रेजों ने 1770 में खोला था।
- 1806 ई. में Bank of Bengal, 1840 ई. में Bank of Mumbai, 1843 ई. में मद्रास में खोला गया, जिसे 1921 ई. में इन तीनों को मिलाकर Imperial Bank की स्थापना की गई।
- 1 July, 1955 को गोरवाला समिति के सिफारिश पर Imperial बैंक का नाम बदलकर SBI कर दिया गया था। इसी वर्ष SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- SBI का मुख्यालय मुम्बई है। सर्वाधिक शाखा, कर्मचारी, धन, ATM, ब्रांच SBI के हैं। प्रारंभ में SBI के आठ सहयोगी बैंक भी थे किन्तु इन्हें SBI में मिला लिया गया।
- भारतीय तथा अंग्रेजों द्वारा मिलकर खोला गया पहला बैंक 1881 ई. में अवध Commercial Bank था।

- किसी भारतीय द्वारा खोला गया पहला भारतीय बैंक (1894) का Punjab National Bank था जिसे लाला लाजपत राय ने खोला।

➤ राष्ट्रीय महिला बैंक

- इसकी स्थापना 19 नवम्बर 2013 को मुम्बई में हुई। इसमें यह प्रावधान था कि खाता धारक केवल महिलायें होगी किन्तु यह बैंक सफल नहीं हो सका। अन्ततः उसे SBI में मिला दिया गया।

Note :- विश्व की पहली महिला Bank Pakistan में 1989 में खोला गया।

➤ बैंक का राष्ट्रीकरण

- प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना राष्ट्रीय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीकरण दो चरणों में हुआ।

➤ प्रथम चरण

- वैसे बैंक जिनकी पूंजी Rs. 50 करोड़ से अधिक थी, उन्हें 1969 में राष्ट्रीकरण कर दिया गया। प्रथम चरण में 14 बैंक का राष्ट्रीकरण हुआ।

क्र०	बैंक	स्थापना
1.	बैंक ऑफ इलाहाबाद	1865
2.	पंजाब नेशनल बैंक	1894
3.	बैंक ऑफ इंडिया	1906
4.	केनरा बैंक	1906
5.	इण्डियन बैंक	1907
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1908
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
8.	यूनियन बैंक	1919
9.	सिंडिकेट बैंक	1925
10.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1935
11.	इण्डियन ओवर सीज बैंक	1937
12.	देना बैंक	1939
13.	यूको बैंक	1943
14.	यूनाइटेड बैंक	1950

➤ द्वितीय चरण

- वैसे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी इनका राष्ट्रीकरण 1980 में हुआ।

दूसरे चरण में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ-

(i) कारपोरेशन बैंक	1906
(ii) पंजाब एवं सिंध बैंक	1908
(iii) आन्ध्रा बैंक	1923
(iv) विजया बैंक	1933
(v) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	1936
(vi) ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1943

Remark :- विजया बैंक तथा देना बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया।

- इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 19 से घटकर 17 हो गई है।
- वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक [RRB (Regional Rural Bank)]

- इसकी स्थापना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर, 1975 को हुई। इसकी कुल संख्या 56 है।
 - सर्वाधिक RRB उत्तर प्रदेश में है।
 - गोवा तथा सिक्किम में RRB नहीं है।
 - 1987 ई. में गठित केलकर समिति के सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया था कि अब RRB की संख्या नहीं बढ़ेगी केवल शाखा बढ़ेगी।
 - RRB का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सस्त ऋण उपलब्ध कराना है।
 - RRB में 50% हिस्सेदारी केन्द्र की, 35% हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक (Promotional Bank) की तथा 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है।
- प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-** उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक इत्यादि।
- केलकर समिति के सिफारिश के अनुसार 1987 ई. में नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापना बंद कर दी गई है।
 - नाबार्ड के परामर्श के अनुसार अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है।

प्राइवेट बैंक (Private Bank)

- ये बैंक RBI के अधीन काम करते हैं। किन्तु इन पर निजी स्वामित्व होता है।
- **ICICI Bank (Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank)**
- इसकी स्थापना 1994 ई. में हुई। इसका मुख्यालय बड़ौदा में है, यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है।

➤ **HDFC Bank (Housing Development Finance corporation Bank)**

- इसकी स्थापना 1994 ई. में हुई। इसका मुख्यालय मुम्बई है। यह निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। सुविधा देने के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है।

➤ **AXIS Bank**

- इसकी स्थापना 1994 ई. में हुई है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। यह निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। UTI बैंक का नाम 2007 में AXIS रख दिया गया। UTI की स्थापना 1964 में हुई थी।

1994 में UTI को दो भागों में बाँटा गया-

1. UTI म्यूचुअल फण्ड
2. UTI बैंक।

विकास बैंक (Development Bank)

- इस बैंक की स्थापना किसी देश की उद्योग और आधुनिक संरचना में विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता है।

भारत में प्रमुख विकास बैंक- आयात-निर्यात बैंक (EXIM Bank), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

➤ **IFCI (Industrial Finance Corporation of India)**

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 1948 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उपक्रमों को मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जिनमें बैंकिंग आवास उपयुक्त हो।

➤ **EXIM Bank**

- यह बैंक केवल आयात-निर्यात के लिए केन्द्र सरकार को धन उपलब्ध करता है। अतः इसे Export Import बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना सन् 1982 में किया गया।

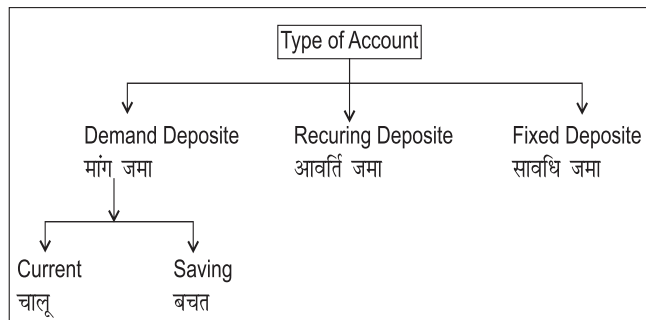
➤ **NABARD (National Bank of Agriculture and Rural Development)**

- इसकी स्थापना 12 जुलाई, 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिशों पर हुई। इसका मुख्यालय मुम्बई में है। यह बैंक न होकर के एक वित्तीय संस्था है।

➤ **SIDBI (Small Industries Development Bank of India)**

- इसकी स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) ऋण प्रवाह को सुविधाजनक एवं मजबूत करना है।

खाता [Account (A/C)]



➤ मांग जमा (Demand Deposit)

☞ इस प्रकार की जमा को कभी भी निकाला जा सकता है।

➤ चालू खाता (Current Account)

☞ यह बिजनेस के लिए होता है। इसमें अधिकतम लेन-देन की सीमा नहीं होती है। इस पर ब्याज नहीं मिलता है।

➤ बचत खाता (Saving Account)

☞ यह छोटे मोटे बचत के लिए होता है। इसमें अधिक धन नहीं रख सकते हैं। इसमें अधिकतम लेन-देन की सीमा निर्धारित रहती है। इस पर लगभग 4% ब्याज दिया जाता है।

➤ आवर्ती जमा [R.D. (Recurring Deposit)]

☞ इसमें एक निश्चित धनराशि को निश्चित समय अंतराल के बाद जमा किया जाता है। इसमें लगभग 6% ब्याज होता है।

➤ सावधि जमा (Fixed Deposit)

☞ इस पर एक निश्चित धन को एक निश्चित समय में एक ही बार में जमा करना होता है। F.D. 7 दिनों से 10 साल तक के लिए जमा हो सकता है। इसपर लगभग 10% ब्याज मिलता है।

➤ KYC (Know Your Customer)

☞ बैंक का बीमा कम्पनी ग्राहक की पहचान के लिए आधार कार्ड, पैनकार्ड या Voter ID मांगती है। जिसे KYC कहते हैं।

➤ बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme)

☞ बैंक से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने एवं समाधान के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई।

➤ बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित किए गए प्रमुख समितियाँ

समितियाँ	उद्देश्य
नरसिम्हन समिति	बैंकिंग संरचना में सुधार
केलकर समिति	आधारभूत संरचना का विकास (PPP) मॉडल
ए. घोष समिति	बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु
गोईपेरिया समिति	ग्राहक सेवा में सुधार हेतु
बिमल जालान समिति	नए बैंक के परमिट हेतु
उषा थोराट समिति	गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध हेतु
नचीकेत मोर समिति	वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु

बीमा (Insurance)

☞ भारत में बीमा की सबसे बड़ी कम्पनी LIC है। इसकी स्थापना 1 September, 1956 को हुई। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।

➤ जनरल इंश्योरेंस बीमा (GIC)

☞ यह बीमा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कम्पनी है। इसकी स्थापना 22 November, 1972 को हुई। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।

➤ बीमा-किस्त (Premium)

☞ LIC के किस्त को प्रिमियम कहा जाता है।

➤ IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority of India)

☞ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की स्थापना 1999 में हुई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका मुख्य उद्देश्य कम्पनी पर निगरानी होता है।

□□□

चेक (Cheque)

- ☞ यह एकाउंट में रखे धन को निकालने का एक साधन है।

Type of Cheque

➤ साधारण चेक (Bearer Cheaque)

- ☞ इस चेक से कैश धन निकलता है। यह जिस व्यक्ति के हाथ में रहता है बैंक उसे धन दे देता है। अतः यह सबसे असुरक्षित चेक है।

➤ अदिस्ट चेक (Order Cheque)

- ☞ इस चेक से भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है, जिस व्यक्ति का नाम इस चेक पर लिखा होता है।

➤ रेखांकित चेक (Cross Cheque)

- ☞ इस चेक के ऊपर बाएं कोने पर दो रेखा खींची जाती है। इस चेक से भुगतान एकाउंट से एकाउंट में होता है। अतः यह सबसे सुरक्षित चेक है।

➤ Gift Cheque

- ☞ इसका आकार बहुत बड़ा होता है। यह पुरस्कार देने के काम में आता है।

➤ Post Dated Cheque

- ☞ वैसा चेक जो लिखे तारीख से अगले तीन महीने तक वैध हो Post Dated Cheque कहलाता है। वर्तमान में सभी Cheque Post Dated cheque होते हैं।

➤ Blank Cheque

- ☞ वैसा चेक जिसपर हस्ताक्षर तो किया हुआ होता है किन्तु धनराशि नहीं लिखी हुई होती है। उसे Blank Cheque कहते हैं।

➤ Cheque Bounce

- ☞ जब चेक में लिखी धन राशि से कम धन राशि एकाउंट में हो तो बैंक ऐसे चेक पर भुगतान नहीं करता है। इसे Cheque Bounce कहते हैं। यह कानूनन अपराध है।

बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)

- ☞ बैंक ड्राफ्ट एक वित्तीय पूंजी है जिसकी सहायता से धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है।
- ☞ बैंक में धन जमा कर कोई भी ड्राफ्ट जारी करवा सकता है तथा ड्राफ्ट का प्राप्तकर्ता अपने जिस बैंक का ब्रांच पर ड्राफ्ट लिखा गया है, को ड्राफ्ट प्रस्तुत करके धन एकत्रित कर सकता है।
- ☞ बैंक प्रायः अन्य स्थानों पर अपनी ब्रांच पर ड्राफ्ट जारी करता है तथा बैंक अन्य बैंक पर भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है। बशर्ते उस बैंक से पहले बैंक का समझौता हो।

- ☞ बैंक ड्राफ्ट जारी करने हेतु बैंक कुछ कमीशन लेता है। बैंक बिना कमीशन भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है। यदि ग्राहक का बैंक से बहुत अच्छा संबंध हो।

कोर बैंकिंग (Core Banking)

- ☞ कोर बैंकिंग का पूरा नाम Core Banking Solution (CBS) या Centralise Banking Solution (CBS) है।
- ☞ इस पद्धति में ग्राहक एक विशेष ब्रांच में खाता खोल कर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना बैंकिंग कार्य करवा सकता है।
- ☞ इस पद्धति में ग्राहक 'ब्रांच का ग्राहक' से 'बैंक का ग्राहक' बन जाता है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फण्ड हस्तांतरण (National Electronic Fund Transer-NEFT)

- ☞ इस पद्धति से व्यक्ति, फर्म या कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फण्ड को एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में भेज सकता है।
- ☞ NEFT में फण्ड को समूहों में निपटारा जाता है तथा निपटारे का काम एक विशेष समय पर किया जाता है।
- ☞ RBI के निर्देशानुसार NEFT सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 11 बार निपटाए जाते हैं। जिसकी अवधि 9:00AM से 2:00 PM निर्धारित की गई है।
- ☞ NEFT सुविधा के अंतर्गत हस्तांतरित किये जाने वाले धन की कोई न्यूनतम व अधिकतम सीमा नहीं है परंतु धन भेजने वाले ग्राहक का NEFT बैंक ब्रांच में खाता नहीं है तो नगरी के बदले उसके द्वारा हस्तांतरित किए जानेवाले धन की सीमा 50,000 रु. है।
- ☞ NEFT सुविधा द्वारा धन भेजने वालों को फीस के साथ सेवाकर देना पड़ता है परंतु धन प्राप्त करने वाले ग्राहक को फीस नहीं देना पड़ता है।
- ☞ NEFT सुविधा द्वारा विदेशों में न तो धन भेजा जा सकता है न ही विदेशों से धन प्राप्त किया जा सकता है।

Real Time Gross Settlement or RTGS

- ☞ NEFT के तरह RTGS द्वारा भी फण्ड को एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच में भेजा जाता है परन्तु RTGS पद्धति में फण्ड को समूहों में नहीं बल्कि एक-एक करके स्वतंत्र रूप से निपटारा जाता है।

- RTGS धन हस्तांतरित करने वाली तीव्रतम पद्धति है परंतु RTGS की सुविधा केवल कोर बैंकिंग सोल्यूशन बैंक ब्रांच पर ही उपलब्ध हो सकती है।
- RTGS व्यवहारों के लिए न्यूनतम राशि सीमा 2 लाख रु. है जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।

MICR Code (Magnetic Ink Character Recognition Code)

- यह मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नीशन प्रतीकों को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी है। जिसका प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों में किया जाता है।

IFSC Code (Indian Financial System Code)

- इन्डियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 अक्षरों का अल्फान्यूमेरिक कोड है जो NEFT, RTGS, ECS प्रणाली में प्रयोग लाया जाता है।
- IFSC कोड में पहला चार वर्णमाला के अक्षर बैंकों के नाम को प्रदर्शित करते हैं तथा अन्तिम छह संख्या अक्षर बैंकों का शाखा को प्रदर्शित करता है। पाँचवा अक्षर शून्य होता है जो भविष्य में प्रयोग के लिए आरक्षित होता है।

SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications code)

- यह एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क है। जिसका उपयोग वित्तीय संस्थान जानकारी को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए किया करते हैं।
- SWIFT कोड का उपयोग दो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच भुगतान के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार घरेलू ट्रांजेक्शन हेतु IFSC कोड का उपयोग किया जाता है।
- SWIFT भुगतान संदेश से जाता है, जिसके आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान एक-दूसरे के खातों के माध्यम से आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
- SWIFT केवल संदेशों को हस्तांतरित करता है न कि धनराशि को।

ATM (Automated Teller Machine)

- ATM ऐसी स्वचालित मशीन है, जिसमें प्लास्टिक कार्ड (डेबिट या क्रेडिट कार्ड) डालने एवं अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) टाईप करके रुपया निकलवाया तथा जमा करवाया जा सकता है।
- भारत के सभी ATM को जोड़ने वाला नेटवर्क को नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं। इस ATM नेटवर्क का संचालन “भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम” करता है।

- इसकी खोज 1967 में जॉन सेफर्ड वारनेश ने किया। भारत में पहला ATM 2004 में SBI ने लाया। इसे कोच्ची में झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया।

ATM के प्रकार

1. बैंक का ATM

- इस ATM का स्वामित्व बैंक के पास होता है और उसका संचालन भी बैंक स्वयं करते हैं। ऐसे ATM में बैंक अपना LOGO लगाते हैं।

2. ब्राउन लेबल ATM

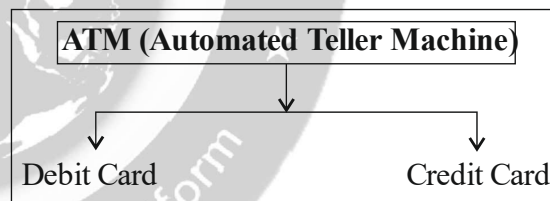
- इस प्रकार के ATM में नगद की व्यवस्था तथा इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था बैंक स्वयं करते हैं तथा शेष काम तीसरे पक्ष द्वारा कार्रवाई जाती है। इस ATM पर भी बैंक अपना लोगो (LOGO) लगाते हैं।

3. व्हाइट लेबल ATM

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी द्वारा संचालित ATM को व्हाइट लेबल ATM कहते हैं। इस पर किसी बैंक का लोगो नहीं लगा रहता है।

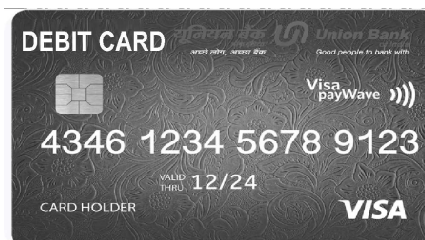
4. माइक्रो ATM

- यह कार्ड स्वाइप मशीन होती है। उसके द्वारा बिल भुगतान किया जाता है। इसे POS (Point of sale) कहते हैं।



➤ Debit Card

- यह हमारे स्वयं खाते में जमा पैसा निकालने का एक आसान तरीका होता है।
- डेबिट कार्ड बहुत ही Secure होता है।
- इसमें 16 Digit का ATM Card Number होता है। इसमें Expiry Date लिखा रहता है। साथ ही इसमें Card Verification Value जिसे CVV कहते हैं। यह एक स्टीकर पट्टी में 3 अक्षर का ATM Card के पीछे होता है।
- इसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 अंक का पिन होता है। जो आपको स्वयं मालूम होना चाहिए।





CVV
NUMBER

➤ Credit Card

- ☞ जिस ग्राहकों पर बैंक का पूरा विश्वास होता है। बैंक उसे ही Credit Card देती है और वह व्यक्ति जब चाहे उस Credit Card से easily loan निकाल सकता है।
- ☞ इसमें बैंक ग्राहकों को एक सीमा (limit) तय करती है।
- ☞ इसमें बैंक ग्राहकों को 25 हजार से 3 लाख तक लोन (Loan) देती है।
- ☞ Credit Card से Loan लेने पर 30-40 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगता है।



➤ RuPay Card

- ☞ यह दो शब्द Rupee अर्थात् रुपया एवं Payment अर्थात् भुगतान से मिलकर बना है।
- ☞ यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के द्वारा शुरू की गयी एक योजना है। इसका मूल उद्देश्य सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एकीकृत करना है।
- ☞ इसकी शुरुआत 2014 में तात्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के द्वारा किया गया था।



➤ ई-रूपी (e-RUPI)

- ☞ यह कैशलेस भुगतान का एक तरीका है, जो लाभार्थी को अपने फोन पर एसएमएस (SMS) या क्यूआर (QR) कोड के रूप में मिलता है।
- ☞ इसकी अधिकतम लेनदेन क्षमता 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है।

☞ यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है।



➤ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

- ☞ यह कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। जिसे क्रिप्टो करेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा जारी किया गया।
- विश्व के प्रमुख ई-रूपी वाले देश-
 1. CBDC- सेंट्रल डॉलर (बहामास)- विश्व का पहला देश
 2. eNaira (नाईजीरिया)
 3. e-CNY (चीन)



□□□

11.

भविष्य निधि PF (Provident Fund)

➤ भविष्य निधि (Provident Fund)

- इसकी स्थापना 1952 में हुई।
- यह एक अनिवार्य सेवा निवृत्ति बचत योजना है जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा किया जाता है।
- इसे खोलने के लिए कर्मचारी कही जाने की जरूरत नहीं है। जब वह पहली बार किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी के तरफ से ही PF खाता खुल जाता है।
- इसमें UAN (Universal Account Number) मिलता है। उस समय कंपनी हर महीने कर्मचारी के मूल्य वेतन का 12% काट कर जमा करती है और खुद भी अधिकतम 12% उस कर्मचारी को PF डालती है। इस पूरे पैसे पर सलाना ब्याज दिया है।

EPF (Employees' Provident Fund)

- ऐसे कंपनी जिसके अन्दर 20 से ज्यादा Employee होते हैं। उसे PF काटना अनिवार्य होता है। इसमें ब्याज काफी अच्छा (8-9%) मिल जाता है। इसके रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है। इसमें रिस्क बहुत कम है।
- कंपनी बदलने से PF Account नहीं बदलता है। नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय यही पैसा मिलता है। जिसे Pension कहते हैं।
- कुछ आपातकाल स्थिति में जैसे-चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा कुछ महत्वपूर्ण परिस्थिति में इससे पैसा निकाल सकते हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की चार कार्यालय हैं। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई। इसमें एक व्यक्ति एक ही Account खोल सकता है।

PPF (Public Provident Fund)

- लोक भविष्य निधि (PPF)
- भारत सरकार ने कंपनी और संगठनों से बाहर असंगठित कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए इसकी स्थापना 1968 में की थी।
- पोस्ट ऑफिस या बैंक में सिर्फ 500 रुपये जमा करके PPF Account खोले जा सकता है। हर साल कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। इस खाते को 15 साल तक चलाया जा सकता है। 15 साल पूरे होने पर अपने खाते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें 7 से 8 प्रतिशत ब्याज मिलती है।

- देश का कोई भी नागरिक (बच्चा, वयस्क या वरिष्ठ) PPF Account खुलवा सकता है। इसमें एक व्यक्ति एक ही Account खोल सकता है।

NPS (National Pension Scheme)

- भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जो 1 जनवरी 2004 से प्रारंभ हुई थी। यह एक Investment Scheme है। जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। NPS को EEE (अंशदान पर निवेश, प्रतिफल, निकासी) तीनों स्थिर में पर कर में छूट है। इसमें ब्याज 9 से 10 प्रतिशत मिलता है। इसमें केवल भारतीय खाता खोल सकता है। इसमें 60 वर्ष के उम्र तक पैसे जमा कर सकते हैं। अवधि पूरा होने पर इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।

ग्रेच्युटी (Gratuity)

- एक कंपनी में लम्बे समय तक काम करने वाले कर्मचारी को Salary, Pension, PF के अलावा ग्रेच्युटी भी दी जाती है।
- ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलना वाला रिवाइड होता है। ग्रेच्युटी का छोटा हिस्सा Salary से कटता है। लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी के तरफ से दिया जाता है। जो कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल तक काम करता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है।
- पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत इसका लाभ उस संस्थान के हर कर्मचारी को मिलता है जहाँ 10 से ज्यादा Employee काम करते हैं।

$$\text{Gratuity} = \frac{(\text{salary} + \text{DA}) \times 15 \times \text{Tenure}}{26 \text{ day}}$$

कैप्चा कोड Captcha Code

- Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart
- Captcha Code की मदद से हम वेबसाइट या किसी भी एप पर हम पता लगा पाते हैं कि Input देने वाला मनुष्य है या फिर Bot. किसी भी Website पर इन्हें सुरक्षा का मकसद से लगाया जाता है।





- ☞ यह एक तरह का Advance Captcha Code है। जिसमें कोई भी अक्षर नहीं भरना होता है बल्कि इसमें सिर्फ चेक बॉक्स यानी सही का चिन्ह लगाना होता है। जो क्लिक करते ही उसका IP Address, E-mail, Phone के आधार पर सॉफ्टवेयर अंदाजा लगा लेता है कि आप मनुष्य है या Bot.

प्रमुख शब्दावली

➤ परिसंपत्ति (Assets)

- ☞ किसी कम्पनी या व्यक्ति के सभी प्रकार के चल तथा अचल संपत्तियों का योग Assets कहलाता है।

➤ Multinational Company (MNC)

- ☞ वैसी कम्पनी जो बहुत से देशों में रहती है उसे MNC कहते हैं। इन्हें ब्लूचिप कम्पनी या ब्रांडेड कम्पनी के नाम से जानते हैं।

➤ Layout (छटनी)

- ☞ जब किसी कम्पनी के सीमांत राजस्व में गिरावट आती है तो उसे लगातार घटा होने लगता है। जिस कारण वह मजदूरों को निकाल देती है। जिसे छटनी या ले आउट कहते हैं।

➤ नई आर्थिक नीति (1991)

- ☞ देश जब स्वतंत्र हुआ तो विदेशी कम्पनियों को भारत के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1975 में सरकार जनता के लिए लुभावनी योजना लाने लगी। जिससे की भारत सरकार का खर्च बढ़ गया। इस पर सरकार ध्यान नहीं दी और 1991 में स्थिति ऐसी आयी कि भारत सरकार के पास मात्र 15 दिन के पैसे बचे थे। अतः सरकार ने Bank of England में भारत का सोना गिरवी रख सके। लगभग 300 करोड़ रुपये लाये इसके बाद ही भारत सरकार ने अपनी नीतियों को बदला जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं।

इसके तहत तीन सुधार किए गए—

1. निजीकरण (Privatisation)

- ☞ इसके तहत सरकार ने रेलवे परमाणु तथा अंतरिक्ष विभाग को छोड़कर शेष विभागों में प्राइवेट कम्पनियों को आने का अनुमति दे दिया। जिससे कि भारत में तेजी से विकास हुआ और सरकारी खर्च बच गया।
- ☞ निजीकरण से सर्वाधिक लाभ इस्पात, विद्युत तथा मोटर उद्योग को हुआ।

2. पूँजीबाजार (Capital market)

- ☞ वैसा बाजार जिसे प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक धन की लागत हो, पूँजीबाजार कहलाता है।

Ex. :- इस्पात, तेलशोधक कारखाना, वायुयान etc.

3. विनिवेश (Reinvestment)

Ex. :- सरकारी सम्पत्ति को निजि हाथ में बेच देना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश से सरकार ने बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिए।

वैश्वीकरण (Globalisation)

- ☞ विदेशी कम्पनियों को भारत में आने की अनुमति देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात शुल्क को घटा दिया।
- ☞ जिस वजह से विदेशी कम्पनियाँ भारत में प्रवेश कर पाई और इससे भारत के छोटे-मोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
- ☞ वैश्वीकरण ने कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाले।
- ☞ वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान उन फसलों को उगाने लगे जिनकी विदेशों में अधिक माँग थी ताकि वे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। जिस कारण भारत में खद्यानों की कमी होने लगी और अनाज महंगे हो गए।
- ☞ वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ बैंकिंग सेक्टर, आइटी उद्योग तथा आटोमोबाइल को हुआ।
- ☞ वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ 1995 के बाद हुआ क्योंकि इस समय इंटरनेट भारत में आ गया था।
- ☞ वैश्वीकरण से हम अधिक निर्यात नहीं कर सके जिस कारण व्यापार घाटा बढ़ने लगा।

उदारीकरण (Liberalisation)

- ☞ निजि तथा विदेशी कम्पनियों को छूट देना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण के कारण ही आयात शुल्क घटा दिया गया।
- टेरिस (Tesrit)
- ☞ आयात पर लगने वाले कर को Tesrit कहते हैं।
- Boom
- ☞ किसी अर्थव्यवस्था में आगे वाले अचानक वृद्धि को Boom कहते हैं।
- Core Sector
- ☞ वैसा उद्योग जो अन्य उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए जरूरी है, उसे Coresector के उद्योग कहते हैं।

इनकी संख्या 8 है—

- | | |
|----------------|------------------------|
| (i) बिजली | (ii) स्टील & Iron |
| (iii) सीमेंट | (iv) कोयला |
| (v) Fertiliser | (vi) पेट्रोलियम उत्पाद |
| (vii) गैस | (viii) पेट्रोलियम |

➤ उपभोक्ता प्रभुत्व

- ☞ एक वैसा बाजार जहाँ कीमत का निर्धारण विक्रेता न करके खरीदार करे उसे उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं यह केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही देखा जा सकता है।

➤ **परिचालन अधिशेष या व्यापार अधिशेष**

- ☞ इसका संबंध उद्योग से है।

$$\text{परिचालन अधिशेष} = \text{आय} - \text{व्यय}$$

- ☞ यदि परिचालन अधिशेष धनात्मक होगा तो उद्योग को लाभ होगा।

➤ **सम्प्राप्ति**

- ☞ किसी उद्योग से होने वाले समस्त लाभ को संप्राप्ति कहते हैं।
- ☞ लाभ स्थिर नहीं होता है बल्कि लाभ गतिशील होता है लाभ के गतिशील का सिद्धांत क्लार्क ने दिया था।
- ☞ मार्शल ने बाजार कीमत का सिद्धांत दिया। बाजार कीमत अति अल्पकालिन होती है।
- ☞ लाभ के नवाचार का सिद्धांत शुम्पीटर ने दिया। इसके अनुसार पुरानी वस्तु का आधुनिकीकरण करके लाभ कमाया जा सकता है।

➤ **लाभ-अलाभ बिंदु**

- ☞ जब किसी फर्म की सिमांत लागत उसके सीमांत सम्प्राप्ति के बराबर हो जाए तो उसे लाभ अलाभ बिंदु कहते हैं।

➤ **Take off Stage**

- ☞ जब किसी कम्पनी का लाभ एक समान दर से आगे बढ़ रहा हो तो उसे Take off कहते हैं।

➤ **विक्रय लागत**

- ☞ किसी वस्तु के विज्ञापन पर किया गया खर्च को विक्रय लागत कहलाता है। यह एक सम्मानीय लागत होता है।

➤ **नवासान वस्तु**

- ☞ बहुत ही जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तु नवासान वस्तु कहलाती है। इनका मांग अति अल्पकालीन होता है।

Ex. :- दुध, सब्जी।



➤ मुद्रा (Currency)

- ☞ यह किसी वस्तु के विनिमय के काम में आती है। यह दो वस्तु में अंतर स्पष्ट कर सकती है। यह गुणवत्ता की पहचान कर सकती है। यह अर्थव्यवस्था का आधार होता है।

मुद्रा के प्रकार (Types of Currency)

➤ धातु मुद्रा (Metal Currency)

- ☞ इस मुद्रा का आंतरिक मूल्य होता है। अर्थात् धातु की अहमियत होती है। इसमें टूट-फूट होने पर मूल्य में अंतर नहीं होता है।
Ex. :- सोना या चांदी का सिक्का।

➤ कागजी मुद्रा (Paper Currency)

- ☞ इस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है बल्कि इसपर किए गए हस्ताक्षर, रंग तथा फोटो का महत्व होता है।
Ex. :- भारत का रुपया।

➤ प्लास्टिक मुद्रा (Plastic Currency)

- ☞ बैंक तथा कम्पनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं।
Ex. :- ATM कार्ड

➤ विधि ग्रह मुद्रा (Legal Tender Currency)

- ☞ किसी देश के अंदर की वैसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना अनिवार्य हो उसे विधि ग्रह मुद्रा कहते हैं।
Ex. :- जापान में येन, भारत में रुपया।

➤ सस्ती मुद्रा (Cheap Money)

- ☞ वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर कम हो सस्ती मुद्रा कहलाती है।
Ex. :- विकासशील देशों की मुद्रा- नेपाल, भारत।

➤ सुलभ मुद्रा (Soft Currency)

- ☞ वैसी मुद्रा जिसका मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो 'सुलभ मुद्रा' कहलाती है।
Ex. :- वेनेजुएला का मुद्रा।

➤ महंगी मुद्रा (Dear Currency)

- ☞ वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर अधिक हो महंगी मुद्रा कहलाती है।

➤ दुर्लभ मुद्रा (Hard Currency)

- ☞ इस मुद्रा का मांग अधिक होता है तथा पूर्ति कम होती है।
Ex. :- डॉलर।

➤ गर्म मुद्रा (Hot Currency)

- ☞ वैसी मुद्रा जिसके मूल्य बहुत तेजी से परिवर्तन हो तथा वह लाभ वाले स्थान पर चली जाय गर्म मुद्रा कहलाती है। इसका प्रयोग बड़े उद्योगपति तथा व्यापारी करते हैं।

➤ प्रतिबंधित मुद्रा (Restricted Currency)

- ☞ वैसी मुद्रा जो IMF के NEER का पालन न करके अपने देश के मुद्रा को स्वतः घटा-बढ़ा देती है, प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है।
Ex. :- चीन का युआन।

➤ Digital Currency

- ☞ वैसी मुद्रा जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो।

Ex. :- Crypto-currency

➤ Crypto-Currency

- ☞ यह एक Virtual मुद्रा है। यह एक विशेष प्रकार की Software से बना है। जिसका केवल Online लेन-देन ही संभव है। सबसे बड़ी Crypto-Currency—Bit Coin है। जिसकी खोज सातोसी नाकामोटो ने किया है।
- ☞ बेन्जुएला की Crypto-currency—Petro है।
- ☞ Facebook की Crypto-currency—Libra है।

विमुद्रीकरण (Demonitisation)

- ☞ जब देश में काला धन अधिक बढ़ जाए तो सरकार नोट बदल देती है। जिससे काला धन स्वतः समाप्त हो जाता है।
- ☞ भारत में सर्वप्रथम 1946 ई. में विमुद्रीकरण किया गया था।
- ☞ स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1978 ई. में मोरारजी देसाई द्वारा किया गया, जबकि दूसरी बार विमुद्रीकरण 8 नवम्बर 2016 को मोदी जी के द्वारा किया गया।

अवमूल्यन (Devaluation)

- ☞ जब अपने देश की मुद्रा को जान-बुझकर गिरा दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं।
- ☞ अवमूल्यन से निर्यात बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि हो जाती है। इससे निर्यातक देश को लाभ होता है किंतु आयतक देश को घाटा होता है।

भारत में तीन बार अवमूल्यन किया गया है—

- 1949
- 1966
- 1991

- ☞ सबसे ज्यादा अवमूल्यन 1991 के दौरान दो चरणों में हुआ।
अवमूल्यन हुआ।

SDR (Special Drawing Right)

- ☞ इसका प्रारंभ IMF ने किया। SDR को कागजी स्वर्ण (Paper Gold) कहा जाता है।
- ☞ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार SDR के पाँच मुद्रा में से किसी एक में हो सकती है।

SDR में निम्न पाँच मुद्राएँ आती हैं—

- (i) \$ (डॉलर) – USA
- (ii) P (पाउण्ड) – ब्रिटेन
- (iii) € (यूरो) – यूरोप
- (iv) ¥ (येन) – जापान
- (v) 元 (युआन / रेंमिन्बी) – चीन

Note :- ₹ यह भारत की अधिकारिक मुद्रा इसका डिजाइन आई.आई.टी बम्बई के उदय कुमार ने किया था। इस चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया था।

□□□



13.

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro-Economy)

- इस अर्थशास्त्र (Micro-Economy) में आर्थिक क्रियाओं जैसे माँग एवं पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण आदि से संबंधित समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है।
- अल्फ्रेड मार्शल को "Father of Micro-Economy" कहा जाता है।

माँग (Demand)

- प्रभावपूर्ण इच्छा को माँग कहते हैं।
माँग को प्रभावित करने वाले कारक—
 - जनसंख्या
 - आय
 - तकनीक
 - मौसम
 - फैशन
 - मूल्य
 - प्रचार
 - ऑफर
- माँग मूल्य का ऋणात्मक या ह्रास माँग फलन होता है अर्थात्

$$\text{माँग} = \frac{1}{f(\text{मूल्य})}$$

माँग के प्रकार—

- स्वतंत्र माँग (Independent Demand)**
- इच्छा पूर्ति के लिए की गई माँग स्वतंत्र माँग कहलाती है।
Ex. :- कार
- व्युत्पन्न माँग (Derived Demand)**
- स्वतंत्र भाग की उपयोगिता की ओर अधिक बढ़ाने के लिए व्युत्पन्न माँग की आवश्यकता होती है।
Ex. :- कार की सीट कभर।
- संयुक्त माँग (Joint Demand)**
- वैसा वस्तु जो एक दूसरे के बिना अधूरी हो उसे पूरक वस्तु कहते हैं और पूरक वस्तु की माँग संयुक्त माँग कहलाती है।
Ex. :- कार, पेट्रोल (जूता-मोजा व्युत्पन्न माँग है न की संयुक्त माँग)
- प्रतिच्छेद माँग (Croze Demand)**
- दो मिलती-जुलती वस्तु को समरूप वस्तु कहते हैं और इसके माँग को Croze माँग कहते हैं।
Ex. :- चाय-काफी, पेप्सी-थमसप।
Remark :- समरूप वस्तु होने से वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ता क्योंकि लोग माँग को बदल देते हैं।

लागत (Cost)

- किसी वस्तु में उपयोगिता सृजन करने के लिए लगाया गया धन लागत कहलाता है।
लागत के प्रकार—
 - कुल लागत (Total Cost)**
 - उत्पादन के लिए किया गया अधिकतम खर्च कुल लागत कहलाता है।
 - औसत लागत (Average Cost)**
 - उत्पादन के लिए खर्च किया गया आवश्यक धन राशि औसत लागत कहलाता है।
 - सीमांत लागत (Marginal Cost)**
 - उत्पादन के लिए किया गया न्यूनतम खर्च सीमांत लागत कहलाता है।
 - अवसर लागत (Opportunity Cost)**
 - किसी चल रहे उद्योग से निकाला गया वह धनराशि जिससे की उस उद्योग पर कोई प्रभाव न पड़े और एक नया उद्योग प्रारंभ हो जाय अवसर लागत कहलाता है। कम्पनी अपना विस्तार इसी लागत से करती है।
 - स्थिर लागत (Fixed Cost)**
 - वैसा लागत जो उत्पादन के बढ़ने घटने से नहीं बदलता है स्थिर लागत कहलाता है। जैसे— मकान का किराया।
 - परिवर्तित लागत (Variable Cost)**
 - वैसा लागत जो उत्पादन के बढ़ने घटने से बढ़ता रहता है परिवर्तित लागत कहलाता है। जैसे— बिजली बिल, कच्चा माल पर खर्च।
 - मूल लागत (Real Cost)**
 - शारीरिक श्रम के रूप में लगाया गया लागत, मूल लागत कहलाता है। 10 रु. में किसी वस्तु को खरीद कर 100 रु. में बेचने पर मुद्रा लागत तो निकल जाता है किन्तु मूल लागत नहीं निकल पाता है। जिस कारण हानि या घाटा हो जाता है।
 - मूल्य (Price)**
 - मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई माँग मूल्य कहलाता है। माँग के बढ़ने से मूल्य बढ़ जाता है। किन्तु मूल्य के बढ़ने से माँग नहीं बढ़ता है।

□□□

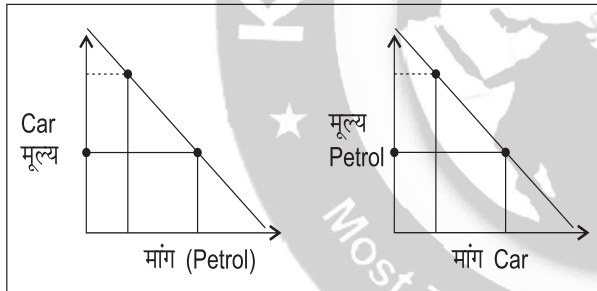
14.

वस्तु (Goods)

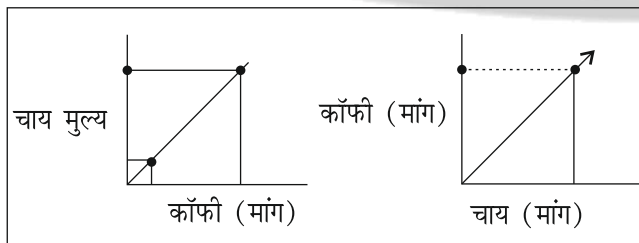
- अर्थशास्त्र में वस्तु को एक ऐसे रूप परिभाषित किया जाता है जिसमें समान मूल्य के उत्पादों के लिए खरीदा एवं बेचा या विनिमय किया जाता है। अर्थ

Types of Goods

- पूरक वस्तु (Complimentary goods)**
- वैसी वस्तु जो एक-दूसरे को पूरा कर दे या एक-दूसरे के बिना अधुरा हो। इस पर मांग का नियम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगता।
Ex. :- मोबाइल और सिम, Car Petrol
- इसमें एक का मूल्य बढ़ने-घटने से दूसरे के माँग पर असर पड़ जाता है।
- इसके ग्राफ में उल्टा संबंध होता है। इसका ढाल ऋणात्मक होता है।



- समरूप/प्रतिस्थापन वस्तु (Substitute Good)**
- यह एक दूसरे के value को गिराते आते हैं। इसमें जब एक का मूल्य बढ़ाएंगे तो व्यक्ति दूसरे का उपयोग करने लगते हैं।
Ex. :- चाय-कॉफी, Jio-Airtel
- इसका ग्राफ सीधा होता है।



- आवश्यक वस्तु (Compulsary Goods)**
- इस वस्तु का मूल्य निर्भर ही नहीं करता है। यह मांग के नियम का पालन नहीं करती है।
Ex. :- दवा, नमक, बिजली।

- विलासिता वस्तु (Luxury Goods)**
- वैसी वस्तु जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति 100% कर देती है। विलासिता वस्तु कहलाती है।
Ex. :- Apple mobile.
- घटिया वस्तु (Inferior Goods)**
- वैसी वस्तु जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति 100% नहीं करती है घटिया वस्तु कहलाती है।
- गिफन वस्तु (Giffen Goods)**
- सबसे घटिया वस्तु को गिफन वस्तु कहते हैं।

मंसूरी कतरनी 7 Star	→ घटिया
सम्भा मंसूरी राशन	→ गिफन

लोच एवं बेलोच

- लोच (Elasticity)**
- जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन किया जाए उसके फलस्वरूप माँग में भी परिवर्तन हो जाए, उसे लोच कहते हैं।

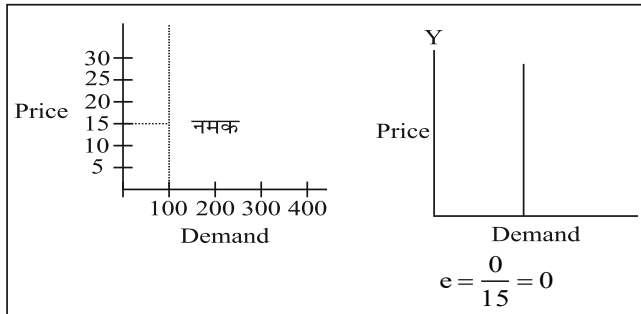
$$\text{लोच } e = \frac{\Delta D}{\Delta P} \begin{matrix} \text{Demand} \\ \text{Price} \end{matrix}$$

- Q. एक वस्तु के मूल्य में 3% कमी की गई। जिसके फलस्वरूप उसके माँग में 12% की वृद्धि हो गई। लोच ज्ञात करें।**

$$e = \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{12}{3} = 4\%$$

- बेलोच (Inelasticity)**
- जब मूल्य में परिवर्तन करने पर भी माँग में परिवर्तन न हो उसे बेलोच कहते हैं।
Ex. :- आवश्यक वस्तु, दवा, नमक।
- बेलोच वस्तुओं के लिए $e = 0$.
- बेलोच वस्तुओं का ग्राफ Y-Axis के समान्तर होता है।
- ईकाई लोच**
- जब मूल्य में परिवर्तन के बराबर परिवर्तन माँग में देखा जाए उसे ईकाई लोच कहते हैं।

- इसमें $e = 1$ होता है।
- ग्राफ 45 अंक के कोण पर एक सरल रेखा प्राप्त करती है।



Remark :- कीमत संतुलन के लिए माँग तथा पूर्ति दोनों का संतुलन होना आवश्यक है।

➤ प्रतिलोच (Cross Elasticity)

- जब दो अलग-अलग वस्तुओं के लोच की तुलना की जाती है उसे Cross इलास्टी कहते हैं।

$$e_{\text{cross}} = \frac{\frac{D_2 - D_1}{D_2 + D_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_2 - P_1}}$$

➤ अधिक लोच

- जब मूल्य में थोड़ा ही परिवर्तन हो किन्तु माँग में परिवर्तन अधिक हो जाय तो उसे अधिक लोच कहते हैं। इसके लिए

$$e > 1 = e = \frac{\Delta D}{\Delta P}$$

➤ अनंत लोच

- जब मूल्य में परिवर्तन न किया जाय और माँग लगातार बढ़ने लगे तो उसे अनंत लोच कहते हैं। $e = \infty$
- यह वास्तविक जीवन में नहीं देखा जाता है इसका ग्राफ X-अक्ष के समांतर होता है।

Note :- अनंत लोच की स्थिति तब आएगा जब किसी वस्तु की पूर्ति को रोक दी जाए।

Q. किसी वस्तु का मूल्य 10 रु. था, तो उसकी माँग 100 थी किन्तु जब उस वस्तु का मूल्य 20 रु. हुआ तो उसकी माँग घटकर 90 हो गई। लोच ज्ञात करें।

$$\text{Ans. } e_{\text{Cross}} = \frac{\frac{90 - 100}{90 + 100}}{\frac{20 - 10}{20 + 10}} = \frac{\frac{-10}{190}}{\frac{10}{30}} = \frac{-10}{190} \times \frac{30}{10} = \frac{-3}{19} = 0.156$$

- यदि उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान उत्पन्न कर सकता है वस्तु बेलोच होगी। जैसे- नमक।
- यदि माँग वक्र दाहिने ओर विस्थापित हो रहा होता है। तो वस्तु की माँग बढ़ रही होती है और मूल्य घट रहा होता है।
- माँग बढ़ने से मूल्य भी बढ़ जाता है किन्तु यदि पूर्ति बनी रहे तो मूल्य नहीं बढ़ता है।

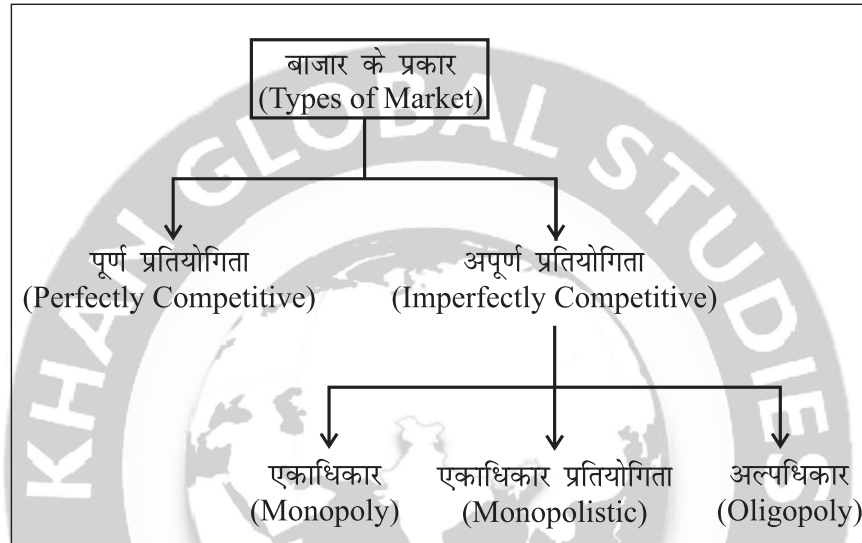
□□□

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

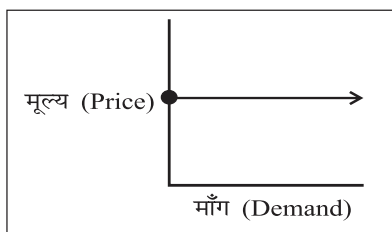
प्रतियोगिता बाजार (Competitive Market)

- जहाँ क्रेता एवं विक्रेता के बीच विनिमय के लिए संबंध स्थापित हो जाए, उसे बाजार कहते हैं।
 - बाजार के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है वह Online भी उपलब्ध है।
- Note :-** बाजार के लिए सबसे जरूरी मूल्य होता है जहाँ मूल्य कम रहेगा बाजार वहीं स्थापित हो जाएगा।



1. पूर्ण प्रतियोगिता (Perfectly Competitive)

- इसमें विक्रेता तथा क्रेता दोनों ही बहुत अधिक होते हैं।
- इस बाजार की निम्नलिखित विशेषता है-**
- इस बाजार में समरूप वस्तुएँ बहुत ही ज्यादा मिल जाती हैं।
- इस बाजार में बिना किसी रूकावट के नये फर्म के प्रवेश की पुरी छूट होती है।
- इस बाजार में वस्तु गतिशील होती है, बाजार में मूल्य बहुत ही कम होती है तथा वस्तु कम मूल्य पर बेची जाती है एवं बाजार में लागत बहुत ही कम होता है।
- इस बाजार में ग्राहक को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
- इस बाजार में ग्राहक को अधिक किन्तु विक्रेता को कम लाभ होता है।
- इस बाजार में माँग लोचदार होती है।
- इस बाजार में वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसी मूल्य पर बेचने की नौबत आ जाती है।



Q. किस बाजार में कीमत को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है?

Ans. पूर्ण प्रतियोगिता

2. अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfectly Competitive)

(i) एकाधिकार (Monopoly)

- इस बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है। जबकि क्रेता की संख्या अनंत होती है।
- Ex. :-** रेलवे, परमाणु ऊर्जा, बिजली, गूगल।
- इस बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-**
- इस बाजार में नये फर्म के प्रवेश पर रोक है।
- इस बाजार में लाइसेंस तथा पेटेंट आवश्यक है।
- इस बाजार में वस्तुएँ बेलोच होती हैं।
- इस बाजार में वस्तु का गतिशील होना आवश्यक है।
- इस बाजार में समरूप वस्तु नहीं मिलती है।
- इस बाजार में ग्राहक को बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
- इस बाजार में मूल्य का निर्धारण कम्पनी करती है।

(ii) एकाधिकार प्रतियोगिता (Monopolistic)

- इस बाजार में एक जैसी वस्तुएँ देखने को मिलती हैं।
- इस बाजार में कई प्रकार की कम्पनियाँ रहती हैं लेकिन उनमें प्रतियोगिता बहुत होती है।

- ☞ इस बाजार में नई कंपनियों का आना मुश्किल होता है।
Ex. :- बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, साबुन, फेसवॉश, शैम्पू।

(iii) अल्पाधिकार प्रतियोगिता (Oligopoly)

- ☞ इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या एक से अधिक होती है। किन्तु क्रेता की संख्या अनंत होती है।
- ☞ इस बाजार में बलदार माँग देखा जाता है।
- ☞ इस बाजार में Quality महत्वपूर्ण रहती है।
- ☞ इस बाजार में सबसे ज्यादा गुटबाजी (Cartel) होती है। इसलिए इस बाजार को Cartel Market भी कहते हैं।
- ☞ इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों के गुण देखे जाते हैं।
- ☞ इस बाजार में मूल्य को लेकर प्रतियोगिता नहीं होती है।
- ☞ इस बाजार में सर्वाधिक प्रचार होता है।

Ex. :- Telcom Company, बड़ी कंपनी।

अन्य प्रमुख बाजार

➤ **द्विपक्षीय एकाधिकार (Bilateral Monopoly)**

- ☞ वैसा बाजार जिसमें क्रेता तथा विक्रेता दोनों के पास शक्ति बराबर हो।

Ex. :- जमीन की खरीद बिक्री, विवाह।

➤ **क्रेता बाजार (Buyer's Market)**

- ☞ वैसा बाजार जिसमें क्रेता को लाभ हो क्रेता बाजार कहलाता है इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में रखते हैं।

➤ **द्वि-विक्रेता बाजार (Double Sellers Market)**

- ☞ इसमें बेचने वाला केवल दो होता है। भारत तथा इण्डियन गैस।

➤ **चोर बाजार (Thief Market)**

- ☞ इसमें पुराने तथा क्षति ग्रस्त चीजों को होल सेल में खरीदकर खुदरा में बेचा जाता है। यह कानूनी रूप से वैध होता है।



16.

उपयोगिता (Utility)

➤ उपयोगिता (Utility)

- आवश्यकताओं की संतुष्टि उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता हमेशा समान नहीं रहती है बल्कि परिवर्तित होती रहती है।
- उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती। उपयोगिता को Utils में मापते हैं। यह Rating System के समान होती है। उपयोगिता अप्रत्यक्ष/परोक्ष (Indirect) रूप से मुद्रा द्वारा मापी जाती है।
- उपयोगिता की सर्वप्रथम जानकारी बेंथम ने दिया था।

उपयोगिता 3 प्रकार की होती है—

- (A) कुल उपयोगिता (Total Utility)
- (B) सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)
- (C) औसत उपयोगिता (Average Utility)

(A) कुल उपयोगिता

- किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं।

(B) सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)

- एक अतिरिक्त इकाई उभोग से उपयोगिता में आने वाली कमी या वृद्धि को सीमान्त उपयोगिता कहते हैं।
- सीमान्त उपयोगिता का सिद्धांत ग्रेसर ने दिया था।

सेब की इकाई	कुल उपयोगिता TU	सीमान्त उपयोगिता MU
1	6	6
2	10	4
3	12	2
4	12	0
5	10	-2
6	6	-4
TU = 56		

Formula :- $TU = \sum MU$

तीसरे इकाई पर कुल उपयोगिता (TU)

$$\begin{aligned}
 &= \sum MU \\
 &= 2 + 4 + 6 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

पांचवें इकाई पर कुल उपयोगिता (TU)

$$\begin{aligned}
 &= \sum MU \\
 &= -2 + 0 + 2 + 4 + 6 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

छठे इकाई पर कुल उपयोगिता (TU)

$$\begin{aligned}
 &= \sum MU \\
 &= -4 - 2 + 0 + 2 + 4 + 6 \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

➤ Case 1

- जब सीमान्त उपयोगिता (MU) धनात्मक (+Ve) हो तो कुल उपयोगिता (TU) बढ़ता है।

➤ Case 2

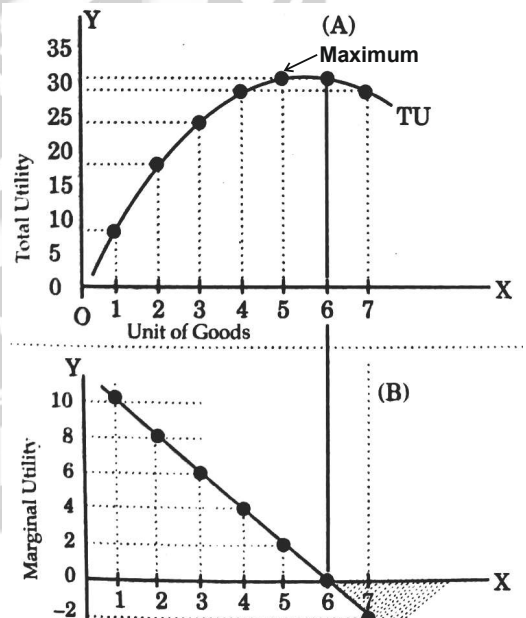
- जब सीमान्त उपयोगिता (MU) शून्य (0) हो तो कुल उपयोगिता (TU) अधिकतम (Max) या तृप्त होती है।

➤ Case 3

- जब सीमान्त उपयोगिता (MU) ऋणात्मक (-Ve) हो तो कुल उपयोगिता (TU) घटती है।

➤ Case 4

- सीमान्त उपयोगिता (MU) तथा मांग में ह्रास नियम होता है।



(C) औसत उपयोगिता (Average Utility)

- कुल उपयोगिता तथा कुल इकाई के अनुपात को औसत उपयोगिता (AV) कहते हैं।
- सीमान्त उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता में सीधा संबंध होता है।

$$AV = \frac{TU}{Q}$$

Q. 10 वस्तु की कुल उपयोगिता 80 Util हो तो औसत उपयोगिता ज्ञात करें।

$$AV = \frac{TU}{Q} = \frac{80}{10} = 8$$

Remark :- जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो प्रारंभ में उसकी उपयोगिता बढ़ती है फिर उपयोगिता नियत हो जाती है और लगातार उपभोग करने से उपयोगिता घटती जाती है।

Ex. :- रोटी खाने पर उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ेगी, फिर घटने लगेगी।

Note :- नशीले पदार्थ, धन, आभूषण, इत्यादि उपयोगिता नियम का पालन नहीं करता है अर्थात् इसके अत्यधिक उपभोग के बाद भी इसे उपयोगिता नहीं घटती है।

Q. किसी वस्तु की उपयोगिता 40 से बढ़कर 52 हो गई हो तो उसकी सीमांत उपयोगिता ज्ञात करें।

Sol. $52 - 40 = 12$

Q. किसी वस्तु के 9 unit की उपयोगिता 25 है जब की 10 unit की उपयोगिता 18 है।

Sol. $18 - 25 = -7$

Q. जब किसी वस्तु की उपयोग में एक इकाई वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर 130 हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी?

Sol. $130 - 100 = 30$

Q. वस्तु x की 9 Unit से कुल उपयोगिता 20 है और 10 Unit से 15 है। 10वें Unit से सीमांत उपयोगिता का परिकलन कीजिए।

Sol. सीमांत उपयोगिता = कुल नई उपयोगिता - कुल पुरानी उपयोगिता
 $= 15 - 20 = -5$

Q. जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता _____ होती है-

- (A) न्यूनतम होती है (B) बढ़ती है
 (C) अधिकतम होती है (D) घटती है

[SSC CPO 2004]

Q. उपयोगिता से अभिप्राय है-

- (A) किसी वस्तु का उपयोगी होना
 (B) किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि
 (C) किसी वस्तु द्वारा सेवा में लाए जाने की क्षमता
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

[SSC MTS 2011]

Q. जब सीमांत उपयोगिता घटती है, तब कुल उपयोगिता-

- (A) घटती है (B) बढ़ती है
 (C) समान रहती है (D) ह्रास दर बढ़ती है

[SSC CHSL 2015]

Q. सीमांत उपयोगिता वक्र है-

- (A) नीचे ढलाननुमा (B) ऊपर ढलाननुमा
 (C) उर्ध्वाधर (D) क्षैतिज

[SSC CPO 2004]

Q. उपयोगिता फलन निम्नलिखित में से किन संबंध को दर्शाता है?

- (A) वस्तुओं के उपभोग की मात्रा और उपभोक्ता की उपयोगिता
 (B) आय और उपभोक्ता की उपयोगिता
 (C) कीमतें और उपभोक्ता की उपयोगिता
 (D) अधिकतम उपयोगिता और कीमतें एवं उपभोक्ता की आय

[SSC CPO 2004]

Q. सीमान्त उपयोगिता और औसत उपयोगिता जब समान होती है।

- (A) बढ़ती है (B) अधिकतम होती है
 (C) ह्रास हो जाती है (D) न्यूनतम होती है

[SSC CGL 2017]

Q. तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है-

- (A) शून्य (B) धनात्मक
 (C) अधिकतम (D) ऋणात्मक

[65th BPSC]

Q. पूर्ण उपयोगिता उस वस्तु की कौन-सी कीमत पर आधारित होती है?

- (A) उपयोग का मूल्य (B) विनियम का मूल्य
 (C) उपरोक्त दोनों (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[SSC CHSL 2017]

Q. जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, तब कुल उपयोगिता होती है-

- (A) बढ़ती हुई (B) अधिकतम
 (C) घटती हुई (D) न्यूनतम

[UPPCS 2017]

Q. किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहा जाता है?

- (A) उपभोग (B) उत्पादन
 (C) निवेश (D) उपयोगिता

[SSC CHSL 2019]

Q. जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है-

- (A) शून्य (B) इकाई
 (C) धनात्मक (D) ऋणात्मक

[SSC CGL 2019]

Q. जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता की स्थिति होगी-

- (A) अधिकतम (B) बढ़ती हुई
 (C) घटती हुई (D) स्थिर

[SSC CHSL 2022]

Q. सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है—

- (A) मूल्य का निर्धारण
(B) मांग का नियम
(C) उपभोक्ता की बचत का आधार
(D) उपरोक्त सभी

[SSC CHSL 2022]

Q. उपभोक्ता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है—

- (A) मुद्रा द्वारा (B) इकाईयों द्वारा
(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

[SSC CGL 2022]

संतुलन की स्थिति

☛ संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जब Market Price पर खरीदी गई वस्तु से हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है।

MRP = पूर्ण संतुष्टि

➤ एक वस्तु की दशा में (One Commodity)

☛ जब उपभोक्ता का सीमांत उपयोग और उसकी मूल्य बराबर हो जाए तो उसे One Commodity कहते हैं।

$$MU_x = P_x$$

जहाँ x = वस्तु, MU_x = वस्तु की सीमांत उपयोगिता

P_x = वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत

➤ मुद्रा की स्थिति में

$$\frac{MU_x}{P_x} = MU_m$$

MU_m = मुद्रा की सीमांत उपयोगिता

Q. उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है तथा केवल वस्तु -Y का उपभोग करता है। वस्तु -Y की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता = 50 युटिल्स एवं $MU_m = 10$ । वस्तु -Y की कीमत ज्ञात कीजिए?

Sol. $\frac{MU_x}{P_x} = MU_m$

$$\frac{50}{Y} = 10$$

$$Y = 5$$

➤ दो वस्तु की दशा में (Two Commodity)

☛ जब पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य का अनुपात तथा दूसरे वस्तु के सीमांत की उपयोगिता और उसके मूल्य का अनुपात समान हो तो उसे Two Commodity कहते हैं।

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} = MU_m$$

$$1. \frac{MU_x}{P_x} > \frac{MU_y}{P_y}$$

☛ यहाँ $\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$ करने के लिए हमें x को ज्यादा उपभोग करना पड़ेगा। क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार अधिक उपयोग करने से उपयोगिता घटती है।

$$2. \frac{MU_y}{P_y} > \frac{MU_x}{P_x}$$

☛ यहाँ $\frac{MU_y}{P_y} = \frac{MU_x}{P_x}$ करने के लिए हमें y को ज्यादा उपभोग करना पड़ेगा। क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार अधिक उपयोग करने से उपयोगिता घटती है।

सीमांत राजस्व

☛ जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या बेचते हैं तो आप मूल्य को बढ़ाते या घटाते हैं तो उससे बिकने वाली वस्तु की मात्रा भी बढ़ या घट जाएगी।

$$\text{सीमांत राजस्व} \rightarrow (P_2 \times Y_2) - (P_1 \times Y_1)$$

Q. यदि एक अधिक मजदूर बढ़ाने पर ईंट निर्माण में उत्पादन की इकाई 2000 से 2250 इकाई प्रतिदिन तक पहुँच जाती है लेकिन ईंट निर्माता को प्रति इकाई दर 15 रु. से 14 रु. तक करनी पड़ जाती है तो उस अंतिम मजदूर का सीमान्त राजस्व होगा—

- (A) 1500 रु. (B) 250 रु.
(C) 3000 रु. (D) 100 रु.

[SSC CHSL 2017]

Sol. ईंट $\rightarrow 2000 - 2250$

मूल्य $\rightarrow 15 - 14$

$$\begin{aligned} \text{सीमांत राजस्व} &\rightarrow (P_2 \times Y_2) - (P_1 \times Y_1) \\ &= (2250 \times 14) - (2000 \times 15) \\ &= 31500 - 30000 = 1500 \end{aligned}$$

उपभोक्ता अधिशेष (Consumer Surplus)

☛ जब ग्राहक वास्तविक मूल्य से भी अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो तो उसे उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं।

$$\text{उपभोक्ता अधिशेष} = \text{इच्छुक कीमत} - \text{वास्तविक कीमत}$$

Q. आलिया को ब्लैक कॉफी पसन्द है। एक दुकान वाले ने आलिया को 120 रु० में 25% छूट पर ब्लैक कॉफी उपलब्ध करायी। यदि आलिया उस ब्लैक कॉफी के 200 रु. देने का इच्छुक थी, तो आलिया का उपभोक्ता अधिशेष है।

- (A) 90 (B) 80
(C) 30 (D) 110

[SSC CHSL 2017]

Sol. इच्छा = 200

वास्तविक कीमत = $120 - 25\% = 90$

CS (उपभोक्ता अधिशेष) = $200 - 90 = 110$

Q. काजोल अपने टीवी को न्यूनतम 7000 रु. की कीमत पर बेचने का इच्छुक थी। काजोल उसे बेचते समय उसकी कीमत 12,000 रु. मांगी, लेकिन वह 10,500 रु. में अंततः बिका। इस लेन-देन में क्या उत्पन्न हुआ?

- (A) 3,500 रु. का उपभोक्ता अधिशेष
(B) 5,00 रु. का उपभोक्ता अधिशेष
(C) 5000 रु. का उत्पादक अधिशेष
(D) 3,500 रु. का उत्पादक अधिशेष

[SSC CHSL 2017]

Q. अनुष्का अपने पुराने टीवी को 37,000 की कीमत तक बेचने का इच्छुक थी। अनुष्का उसे बेचते समय 50,000 रु. का मूल्य रखी, लेकिन वह 42,000 की कीमत पर बिका। इस लेन-देन में उत्पन्न हुआ?

- (A) 5000 रु. का उपभोक्ता अधिशेष
(B) 8000 रु. का उपभोक्ता अधिशेष
(C) 5000 रु. उत्पादक अधिशेष
(D) 8000 रु. का उत्पादक अधिशेष

[SSC CHSL 2017]

Q. कंगना एक प्रतिष्ठान डिजाइनर द्वारा डिजाइन कपड़े खरीदना चाहती है। बाजार में उन कपड़ों की कीमत 5000 रु. है और उस पर दुकान वाला 20% छूट प्रदान कर रहा है। यदि कंगना उस ड्रेस के लिए 7000 रु. तक वाहन कर सकती थी, तो कंगना के लिए उपभोक्ता अधिशेष होगा।

- (A) 3000 रु. (B) 2000 रु.
(C) 1000 रु. (D) 7000 रु.

[SSC CHSL 2017]

Q. कीमतों में बढ़ोतरी से होगा—

- (A) उपभोक्ता अधिशेष में बढ़ोतरी
(B) उपभोक्ता अधिशेष में ह्रास
(C) उपभोक्ता अधिशेष पर कोई प्रभाव नहीं
(D) उत्पाद अधिशेष में ह्रास

[SSC CHSL 2017]

Q. परिणिती को शादी में पहनने के लिए एक वस्त्र इतना पसन्द आया कि वह उसके 30,000 रु. तक वहन करना चाहती थी। उसे वह वस्त्र एक स्थानीय दुकान में 25,000 रु. की दर पर मिल गया। वह उस दुकान से कीमत पर भी 30% छूट प्राप्त कर रही है। यहाँ उपभोक्ता अधिशेष होगा?

- (A) 5000 रु. (B) 12,500 रु.
(C) 7500 रु. (D) 25,500 रु.

[SSC CHSL 2017]

□□□

Most Trusted Learning Platform



KHAN SIR



आगम और उत्पादन (Revenue and Production)

आगम (Revenue)

- ☞ किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बदले ली गई धन-राशि को आगम/सम्प्राप्ति (Revenue) कहते हैं।

आगम के प्रकार-

1. कुल आगम (Total Revenue)
2. सीमांत आगम (Marginal Revenue)
3. औसत आगम (Average Revenue)

1. कुल आगम (Total Revenue = TR)

- ☞ किसी फर्म द्वारा वस्तु की बेची गई मात्रा को कीमत से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे कुल आगम (TR) कहते हैं।

$$\text{कुल आगम} = \text{उत्पादन की मात्रा} \times \text{उत्पादन का मूल्य}$$

$$TR = Q \times P$$

2. सीमांत आगम (Marginal Revenue = MR)

- ☞ किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम (MR) कहते हैं।

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

$$MR = \text{Next TR} - \text{PreTR}$$

3. औसत आगम (Average Revenue = AR)

- ☞ कुल आगम में बेची गई मात्रा का भाग लेने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत आगम (AR) कहते हैं।

$$AR = \frac{TR}{Q}$$

$$\text{औसत आगम} = \frac{\text{कुल आगम}}{\text{बेची गई मात्रा}}$$

Qty.	Price	TR	MR	AR
1	10	10	10	10
2	8	16	6	8
3	6	18	2	6
4	4	16	-2	4
5	2	10	-6	2

उत्पादन (Production)

- ☞ किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है।

उत्पादन के कुल चार कारक हैं-

1. भूमि
2. श्रमिक
3. उद्यमी
4. पूँजी

➤ उत्पादन फलन (Production function)

- ☞ उत्पादन तथा उत्पादन साधनों के मध्य पाया जाने वाला फलनिक भौतिक तथा गणितीय संबंध उत्पादन फलन कहलाता है।

उत्पादन के प्रकार-

1. कुल उत्पादन (Total Production)
2. सीमांत उत्पादन (Marginal Production)
3. औसत उत्पादन (Average Production)

1. कुल उत्पादन (Total Production = TP)

- ☞ एक निश्चित अवधि में सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं।

$$TP = \sum MP \quad (\text{कुल उत्पादन} = \text{सीमांत उत्पादन का जोड़})$$

$$TP = AP \times Q \quad (\text{कुल उत्पादन} = \text{औसत उत्पादन} \times \text{श्रम की मात्रा})$$

2. सीमांत उत्पादन (Marginal Production = MP)

- ☞ श्रम की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं।

$$MP = \text{Next TP} - \text{Pre TP}$$

3. औसत उत्पादन (Average Production = AP)

- ☞ कुल उत्पादन में श्रमिकों की मात्रा का भाग लगाने पर प्राप्त भागफल औसत उत्पादन कहलाता है।

$$AP = \frac{TQ}{QL}$$

$$\text{औसत उत्पादन} = \frac{\text{कुल उत्पादन}}{\text{श्रम की मात्रा}}$$

Machine	Quantity	TP	MP	AP
1	300	300	300	300
2	340	680	680	340
3	400	1200	320	400
4	520	2080	880	520
5	600	3000	920	600

Q ↑ P ↓	Q ↑ P ↑
Q ↓ P ↓	Q ↓ P ↑

संतुलन (Balance Revenue)

- इस स्थिति में पूर्ति (Supply) को मांग (Demand) के बराबर रखना होता है।
 - पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में Supply, Demand के बराबर होता है।
 - सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर होता है।
- Q. यदि ट्रैकिंग बूट का माँग वक्र $D = 11000 - 30 P$ और आपूर्ति $S = 4,000 + 40 P$ ऐसी स्थिति में संतुलन मूल्य क्या होगा?

Sol. $D = S$
 $11000 - 30 P = 4000 + 40 P$
 $11000 - 4000 = 40 P + 30 P$
 $7000 = 70 P$
 $70 P = 7000$
 $P = \frac{7000}{70}$
 $P = 100$ Ans.

- Q. रैसिंग साइकिल के लिए माँग वक्र $D = 59600 - 6P$ और आपूर्ति $S = 29,600 + 4P$ ऐसी स्थिति में संतुलित मात्रा क्या होगी।

Sol. $D = S$
 $59600 - 6 P = 29600 + 4P$
 $59600 - 29600 = 4P + 6 P$
 $30000 = 10 P$
 $10 P = 30000$

$$P = \frac{30000}{10} = 3000$$

$$S = 29600 + 4P$$

$$= 29600 + 4 \times 3000$$

$$= 29600 + 12000$$

$$= 41600 \text{ Ans.}$$

- Q. यदि ट्रैकिंग बूट के लिए माँग वक्र $D = 67500 - 18 P$ और आपूर्ति वक्र $S = 22500 + 12 P$ ऐसी स्थिति में संतुलन मूल्य क्या होगा?

Sol. $D = S$
 $67500 - 18 P = 22500 + 12P$
 $67500 - 22500 = 12P + 18 P$
 $45000 = 30 P$
 $30 P = 45000$
 $P = \frac{45000}{30} = 1500 \text{ Ans.}$

□□□

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

शेयर बाजार (Stock Exchange)

- इसे Stock Market कहते हैं। ये मुम्बई के बर्ली में स्थित है जिसे दलाल स्ट्रिट कहते हैं। शेयर बाजार सुबह 9:15 AM पर खुलता या तथा 3:30 पर बंद हो जाता है। Saturday, Sunday शेयर Market Close रहता है। इसमें पैसा लगाने के लिए Demet Account होना आवश्यक है।
- शेयर में होने वाले Profit को डिबिडेन्ट कहते हैं।
- शेयर की खरीद बिक्री Freefloat के आधार पर की जाती है अर्थात् शेयर को न तो जबरदस्ती खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। कम्पनी को जितने धन की आवश्यकता होती है उसका वह छोट-छोटा टुकड़ा कर देती है जिसे शेयर कहते हैं।

Ex. :- Factory – 10 लाख
Company – 4 लाख
आवश्यकता – 6 लाख
Share – 500 Rs.
Total Share – 1200

- भारत में शेयर बाजार SEBI के नियंत्रण में कार्य करते हैं।
- शेयर बाजार को मुद्रा बाजार या Stock बाजार भी कहते हैं।
- शेयर बाजार एक संगठित बाजार है जहाँ कम्पनियों, सरकार व अर्द्ध सरकारी संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। प्रत्येक शेयर बाजार की एक प्रबन्ध समिति होती है। शेयर बाजार के सभी व्यवहार समिति के नियंत्रण में होते हैं। प्रबन्ध समिति की कम्पनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (Listing) करते हैं। बिना कम्पनी को सूचीबद्ध कराये, उस कम्पनी के शेयर को नहीं बेचा जा सकता है।
- शेयर बाजार का सबसे बड़ा फायदा यह है, निवेशक जब चाहे प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे निवेश को धन में बदल सकते हैं।
- शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूति का व्यवहार (खरीद-बिक्री) सब्सिडियरी जेनरल लेजर (SGL) के माध्यम से होता था परन्तु 1994 से इन प्रतिभूति में व्यवहार थोक ऋण बाजार के माध्यम से होता है।
- जब कोई निवेशक प्रतिभूतियों का क्रय उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से करते हैं तो इसे सट्टा कहा जाता है। शेयर बाजार में नियमों के अधीन सट्टा भी लगाने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange)

- BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है जिसको स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1956 में इसे शेयर बाजार की मान्यता दिया।

- BSE के सूचकांक (INDEX) को BSE Sensitive Index या SENSEX कहते हैं। इसमें 5500 से अधिक कंपनी है किन्तु 30 बड़ी कंपनी को सेंसेक्स में रखते हैं। यह सूचकांक 30 बड़ी कम्पनी के शेयर पर आधारित है जिसकी शुरुआत 1986 में हुआ था।
- शेयर बाजार का सूचकांक शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है। यदि सूचकांक बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है, निवेशक यह मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है और कम्पनियां भविष्य में लाभ अर्जित करेगा।
- BSE में शेयर खरीद-बिक्री हेतु ऑन-लाइन ट्रेडिंग की भी व्यवस्था है।

राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) National Stock Exchange

- BSE में केवल बड़े-बड़े कम्पनी का ही शेयर बिकते थे अतः शेरवानी कमिटी के सिफारिश पर NSE की स्थापना नवम्बर 1992 में एक Public Limited कम्पनी के रूप में किया गया।
- NSE में ट्रेडिंग हेतु कोई विशेष स्थान नहीं है, यह शेयर बाजार पूरे देश के प्रमुख शहरों में अपनी टर्मिनल स्थापित किए हैं। निवेशक किसी भी टर्मिनल पर जाकर पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत माध्यम से शेयर खरीद-बेच सकते हैं। किसी एक शेयर का मूल्य NSE के सभी टर्मिनल पर समान होते हैं।
- NSE के सूचकांक को NIFTY कहते हैं जो NSE में 1500 कंपनी हैं। किन्तु 50 सबसे बड़ी कंपनी को NIFTY में रखते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुम्बई में है।

NSE के प्रवर्तक निम्न हैं—

1. IDBI
2. IFCI
3. ICICI
4. LIC
5. GIC
6. The SBI Capital Market Limited
7. The Stock Holding Corporation of India Limited
8. The Infrastructure Leasing and Financial Limited

शेयर बाजार पर ट्रेडिंग निम्न 5 चरणों में पूरा होता है—

1. शेयर बाजार में शेयर की खरीद-बिक्री करने के लिए सर्वप्रथम, दलाल (Broker) का चयन करना पड़ता है।
- दलाल का सेबी में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

☞ दलाल एक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, बैंक अथवा कंपनी हो सकता है।

Ex. :- Grow, Zirodha, Angel etc.

2. शेयर की खरीद-बिक्री हेतु डिमेट खाता (Demate Account) खोलना अनिवार्य है। इसी डिमेट खाता में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखा जाता है या निकाला जाता है।

☞ इस समय भारत में दो डिपॉजिटरी संस्थान (Depository Insitution) है, जो डिमेट खाता खोलती है।

1. National Securities Depository Limited (NSDL)

2. Central Depository Services Limited (CDSL)

☞ निवेशक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से इन डिपॉजिटरी संस्थान के संपर्क में आते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट SEBI के अनुसार, दलाल, बैंक या अन्य संस्था हो सकता है।

3. **आदेश देना (Placing an order)**— डिमेट खाता खुलते ही निवेशक दलाल को प्रतिभूति खरीद/बिक्री हेतु आदेश दे सकता है। यह आदेश व्यक्तिगत रूप से, मोबाइल/लैंडलाइन अथवा ई-मेल पर दी जा सकती है।

☞ आदेश देते समय निवेशक दलाल को क्रय/विक्रय की जानेवाली शेयर की जानकारी देता है और यह भी बता देता है कि सौदा किस मूल्य तक करना है।

4. आदेश को पूरा करने के बाद दलाल एक Contract Note तैयार करता है और हस्ताक्षरित करके निवेशक को दे देता है। निवेशक इस Contract Note को अपने पास Proof of Transaction के रूप में रखता है।

☞ Contract Note में क्रय-विक्रय की जाने वाले शेयर के नाम, उनकी संख्या उनका मूल्य तथा दलाली (Brokerage) लिखी रहती है।

5. **निबटारा (Settlement)**— शेयर बाजार में शेयर को खरीद-बिक्री का यह अंतिम चरण है। निबटारा का अर्थ है शेयर, विक्रेता के डिमेट खाते से क्रेता के डिमेट खाते में चला जाना।

☞ यदि शेयर बाजार में प्रतिभूति में व्यवहार निर्धारित समय (9:55 am to 3:30 pm) के पूर्व या पश्चात् किया जाता है तो इसे कर्ब ट्रेडिंग (Kerb Trading) कहते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange Board of India (SEBI)

☞ निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार को नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पूंजी अधिनियम, 1947 पारित कर इसे लागू किया गया। लेकिन यह अधिनियम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा।

☞ शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना की गई।

सरकार द्वारा सेबी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य निम्न थे—

1. शेयर बाजार पर नियंत्रित स्थापना कर, वहाँ पर व्यवहार करने वाले सभी पक्षकार को कुशल सेवा उपलब्ध कराना।
2. सेबी का प्रथम उद्देश्य है निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करना क्योंकि निवेशकों के अभाव में शेयर बाजार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
3. आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना और करने वाले को दंडित करना।
4. दलालों पर नियंत्रण रखना।

➤ आंतरिक ट्रेडिंग (Insider Trading)

☞ कम्पनियों के संघर्ष में गुप्त जानकारी रखने हेतु दलाल सट्टेबाजी के दौरान प्रतिभूति खरीद/बिक्री करता है, तो वह हमेशा लाभ की स्थिति में ही रहता है जिसमें आम निवेशकों के हितों को ठेस पहुँचाती है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं।

➤ SEBI के कार्य

1. शेयर बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहार (गलत तरीके से खरीद/बिक्री) को रोकना तथा आचार-संहिता (Code of Conduct) लागू करना।
2. दलाल, उप-दलाल, एजेंट का रजिस्ट्रेशन करना।
3. निवेशकों को खरीद/बिक्री करने हेतु सूचनाएँ उपलब्ध करवाना तथा प्रतिभूति में व्यवहार संबंधी शिक्षा प्रदान करना।
4. शेयर बाजार का अंकेक्षण (Audit) करना।
5. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना।

Mutual Fund

☞ यह ऐसी संस्था है जो छोटे निवेशकों से धन एकत्र करके शेयर बाजार में निवेश करती है।

☞ यह एक निश्चित तिथि के बाद समाप्त हो जाती है।

☞ Mutual Fund का आरंभ 1964 ई. में Unit Trust of India (UTI) की स्थापना के साथ हुआ।

☞ Mutual Fund की देख-रेख Fund Manager करते हैं। जिसे कम से कम 20-30 वर्ष का अनुभव होता है।

☞ यह पैसा आम आदमी से लेता है और उसके लाभ का 2% हिस्सा लेता है।

☞ Mutual Fund 10-12% Return देता है।

SIP (Systematic Investment Plan)

☞ यह एक प्रकार के निवेश का माध्यम है। जिससे Mutual Fund में समय-समय पर छोटी राशि निवेश करने की इजाजत मिल जाती है। इसमें कम-से-कम 500 रु. से निवेश शुरू होता है।

- ☞ यह निवेश साप्ताहिक, मासिक, तिमाही या वार्षिक कोई भी हो सकती है।
- ☞ यह हर साल में 8-10% Return देता है।
- **तेजड़िया (Bull)**
- ☞ यह शेयर के उठने की प्रतीक्षा करता है।
- **मंदरिया (Bear)**
- ☞ यह शेयर की गिरने की प्रतीक्षा करता है।
- **Instidier Tranning**
- ☞ यह एक दण्ड का नाम है यह SEBI वैसे अधिकारी को देती है। जो कम्पनी के गोपनीय सेवाओं को उजागर कर देते हैं।
- **Equity**
- ☞ किसी कम्पनी में किसी व्यक्ति का जितना अधिकार होता है। उसे Equity कहते हैं।
- **डिबेन्चर (Bond)**
- ☞ बड़ी-बड़ी कम्पनी द्वारा दिए गए ऋण का ऋणपत्र ही Bond या डिबेन्चर कहलाता है।
- **चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond)**
- ☞ इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले गुप्त चंदा को रोकना है। चुनावी बॉण्ड केवल 15 दिनों के लिए वैध होते हैं।

विश्व के प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स

1. **डीजोन्स-** न्यूयॉर्क (USA) स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है जो 30 कम्पनियों के शेयर पर आधारित है। यह व्यापक रूप से पूरे विश्व में देखे जाने वाला सूचकांक है।
2. **नॉसडाक (Nasdaq) कम्पोजिट इंडेक्स-** यह USA के शेयर बाजार का सूचकांक है जिसकी शुरुआत 8 फरवरी, 1971 को हुई।
3. **S&P-500-** इस इंडेक्स में USA सटॉक मार्केट की 500 बड़ी कम्पनी के शेयर शामिल हैं।
4. **FTSE100-** यह लन्दन स्टॉक मार्केट का सूचकांक है जो यूरोपीयन मार्केट की गतिविधियों पर प्रकाश डालता है।
5. **निक्की-** यह टोकियो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है।
6. **मिडडेक्स-** फैंकफर्ट (जर्मनी)
7. **हैग सेना-** हांगकांग
8. **सिमेक्सव स्टेटन टाइम्स-** सिंगापुर
9. **KOSPI-** दक्षिण कोरिया
10. **SET-** थाइलैंड
11. **शेन्जेन एवं संधाई-** चीन

बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व के पाँच बड़े स्टॉक एक्सचेंज-

1. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज
2. NASDAQ
3. टोकियो स्टॉक एक्सचेंज
4. लन्दन स्टॉक एक्सचेंज
5. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

महारत्न (Maharatna)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर महारत्न का दर्जा दिया जाता है-

1. कम्पनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये।
2. कम्पनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India-SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिये।
3. पिछले तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रूपए से अधिक होना चाहिये।
4. पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रूपए से अधिक होना चाहिए।
5. पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रूपए से अधिक होना चाहिए।
6. कम्पनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये।

महारत्न कम्पनियाँ

1. Bharat Heavy Electricals Limited (New Delhi)
2. Bharat Petroleum Corporation Limited (Mumbai)
3. Coal India Limited (Kolkata)
4. GAIL India Limited (New Delhi)
5. Hindustan Petroleum Corporation Limited (Mumbai)
6. Indian Oil Corporation Limited (New Delhi)
7. NTPC Limited (New Delhi)
8. Oil & Natural Gas Corporation Limited (New Delhi)
9. Power Finance Corporation (New Delhi)
10. Power Grid Corporation of India Limited (Gurgaon)
11. Steel Authority of India Limited (New Delhi)
12. Rural Electrification Corporation Limited (New Delhi)
13. Oil India Ltd (Duliajan, Assam)

नवरत्न (Navratna)

- ☞ नवरत्न का दर्जा पहली बार 1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) के एक समूह को दिया गया था। वर्तमान में भारत में 13 नवरत्न कम्पनियाँ हैं।

भारत में नवरत्न कंपनियों की पात्रता मानदंड

- ☞ कंपनी के पास मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए।
- निम्नलिखित छह प्रदर्शन मापदंडों की गणना करते समय इसका समग्र स्कोर 100 में से 60 या उससे अधिक होना चाहिए—
- (i) नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट
- (ii) टर्न ओवर के रूप में सकल लाभ
- (iii) उत्पादन या सेवाओं की लागत के लिए जनशक्ति लागत
- (iv) प्रति शेयर आय
- (v) नियोजित पूँजी के रूप में सकल मार्जिन
- (vi) अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन तुलना

नवरत्न कम्पनियाँ

1. Bharat Electronics Limited (Bengaluru)
2. Container Corporation of India Limited (New Delhi)
3. Engineers India Limited (New Delhi)
4. Hindustan Aeronautics Limited (Bengaluru)
5. Mahanagar Telephone Nigam Limited (New Delhi)
6. National Aluminium Company Limited (Bhubaneswer)
7. National Buildings Construction Corporation Limited (New Delhi)
8. Neyveli Lignite Corporation Limited (Tamil Nadu)
9. National Mineral Development Corporation (NMDC) Limited (Hyderabad)
10. Rashtriya Ispat Nigam Limited (Visakhapatnam)
11. Shipping Corporation of India Limited (Mumbai)
12. Rail Vikas Nigam Limited (New Delhi)
13. ONGC Videsh Ltd (New Delhi)
14. Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (Mumbai)
15. IRCON International Limited (New Delhi)
16. RITES Limited (Gurugram)

मिनीरत्न (Miniratna)

मिनीरत्न श्रेणी-1	मिनीरत्न श्रेणी-2
मिनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।	पिछले तीन वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया है और सकारात्मक Net worth होना चाहिए।
इसकी संख्या 62 है।	इसकी संख्या 12 है।

व्यापारिक चिन्ह तथा गुणवत्ता मानक

1. **हॉलमार्क**
- ☞ यह सोने की बनी वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए होता है।
2. **रजतमार्क**
- ☞ यह चाँदी की वस्तुओं के गुणवत्ता के लिए होता है।
3. **Ecomark**
- ☞ यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है।
4. **Agmark**
- ☞ यह कृषि से संबंधित पदार्थों के गुणवत्ता के लिए होता है।
5. **Fssai**
- ☞ यह खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता को निर्धारित करती है।
6. **ISI mark**
- ☞ यह चिह्न औद्योगिक उत्पाद पर लगाया जाता है।

7. FPO mark

- ☞ यह फल उत्पाद पर लगाया जाता है।

8. Non-pollution Vehicle mark या Bharat Stage (BS) II, III, IV, V, VI

- ☞ यह ऑटो वाहनों को प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है कि यह वाहन इस सीमा तक प्रदूषण नहीं फैलाता है।

Indian Standard Organisation (ISO)

- ☞ यह NISO के अधिन कार्य करती है तथा गुणवत्ता संबंधित मानक जारी करती है। जिसे ISO के नाम से जानते हैं।
- ISO – 9001 = प्रबंधन
- ISO – 14001 = पर्यावरण प्रबंधन
- ISO – 9202 = आभूषण की शुद्धता
- ISO – 18001 = स्वास्थ्य सुरक्षा

ISO – 22000 = खाद्य सुरक्षा

ISO – 27001 = सुरक्षा

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

- ☞ IMF का प्रादुर्भाव यू.एस.ए. के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटनवुड्स समझौते के तहत जुलाई, 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुआ।
- ☞ इसका उद्घाटन 27 दिसंबर, 1945 को हुआ तथा इसने 1 मार्च, 1947 के कार्य करना प्रारंभ किया।
- ☞ इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है।
- ☞ वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं और अण्डोरा इसका 190वां देश है।
- ☞ इसकी प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड हैं।
- ☞ भारत IMF का **संस्थापक सदस्य** है।
- **उद्देश्य**
 - ☞ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना।
 - ☞ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना।
 - ☞ अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करना।
- **अन्य**
 - ☞ भारत IMF के 10 बड़े कोटिधारक देशों में शामिल है। भारत का स्थान 8वां है।
 - ☞ वर्तमान में भारत का कोटा 2.44% से बढ़कर 2.78% तथा मताधिकार 2.34% से बढ़कर 2.66% हो गया है।
- **SDR**
 - ☞ 1971 में IMF ने पत्र मुद्रा जारी किया, जिसे अब भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है।
- **IMF द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमुख रिपोर्ट्स**
 1. विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट (World Economic Outlook Report)
 2. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report)

विश्व बैंक (World Bank)

- ☞ विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 27 दिसंबर, 1945 ई. को हुआ।
- ☞ 1946 से विश्व बैंक ने कार्य करना आरंभ किया और इसका मुख्यालय **वाशिंगटन डी.सी.** में है।
- ☞ वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं।
- ☞ तुवालू, दक्षिण सूडान तथा नौरू इसके नवीनतम सदस्य हैं।
- ☞ वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं।
- ☞ यह IMF कोष की **सहसंस्था** है।
- ☞ विश्व बैंक एवं IMF को दो **ब्रिटेनवुड्स की जुड़वा संतानें** कहा जाता है।

विश्व बैंक समूह में पांच संस्थाएँ हैं जिनसे मिलकर विश्व बैंक बनता है—

1. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)
2. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
4. बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेंसी (MIGA)
5. निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (ICSID)

Note:— भारत IBRD, IDA, IFC तथा MIGA का सदस्य है परन्तु ICSID का सदस्य नहीं है।

➤ विश्व बैंक के कार्य

- ☞ आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध करना।
- ☞ भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना।
- ☞ विश्व बैंक का प्रधान कार्य सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराना है।

Notes :— विश्व बैंक समूह से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश भारत है।

- ☞ भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता की मध्यस्था 1960 ई. में विश्व बैंक के द्वारा ही किया गया था।

➤ विश्व बैंक के प्रमुख रिपोर्ट

1. विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)
 2. व्यापार सुगमता रिपोर्ट (Doing Business Report)
- (वर्तमान में इसका प्रकाशन नहीं हो रहा है।)

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank)

- **स्थापना**
 - ☞ संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर, 1966 में की गई थी। 1 जनवरी, 1967 में ADB ने कार्य करना प्रारंभ किया।
- **मुख्यालय**
 - ☞ फिलीपींस की राजधानी **मनीला** में।
- **उद्देश्य**
 - ☞ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना है।
- **अध्यक्ष**
 - ☞ जापान के मात्सुगु असकावा।
- Note :—** ADB का अध्यक्ष पद किसी जापानी नागरिक को ही दिया जाता है।
- **सदस्य**
 - ☞ ADB का सदस्य एशियाई देशों के साथ-साथ अन्य महाद्वीप का भी हो सकता है। वर्तमान में ADB के 68 सदस्य हैं। यह एक **बहुपक्षीय विकास बैंक** है।

एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB - (Asia Infrastructure Investment Bank)

- **स्थापना**
 - ☛ 25 दिसंबर, 2015
- **मुख्यालय**
 - ☛ बीजिंग (चीन)
- **उद्देश्य**
 - ☛ यह बैंक विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती मांग को पूरा करेगा।
 - ☛ यह सदस्य देशों में ऊर्जा, परिवहन तथा वृहद् परियोजना के निवेश की मांग को पूरा करेगा।
- **अध्यक्ष**
 - ☛ चीन के जिन लिक्यून इसके अध्यक्ष हैं।
- **सदस्य**
 - ☛ सदस्यों की कुल संख्या 109 है। (57 संस्थापक सदस्य देश)

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation)-WTO

- **स्थापना**
 - ☛ 1 जनवरी, 1995
- **मुख्यालय**
 - ☛ जेनेवा।
- **उद्देश्य**
 - ☛ वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार का प्रसार करना।
 - ☛ जीवन स्तर में वृद्धि करना।
 - ☛ सतत् विकास तथा संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करना।
- **विश्व व्यापार संगठन के कार्य**
 - ☛ व्यापार एवं प्रशुल्क के मसले पर सदस्य देशों से विचार विमर्श।
 - ☛ विश्व व्यापार समझौता तथा बहुपक्षीय समझौतों का कार्यान्वयन और प्रशासन करना।
 - ☛ व्यापार एवं प्रशुल्क सम्बन्धित विवादों के निपटारे करना।
 - ☛ व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।
- **सदस्य**
 - ☛ वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 164 है। इसके नवीनतम सदस्य लाइबेरिया तथा अफगानिस्तान है, जिन्हें क्रमशः 14 जुलाई, 2016 तथा 29 जुलाई 2016 को शामिल किया गया है।
- **विश्व व्यापार संगठन एवं मंत्रीस्तरीय सम्मेलन**
 - ☛ WTO की सबसे बड़ी निर्णायक एवं नीति-निर्माण संस्था सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्रियों का सम्मेलन है।
 - ☛ इसकी बैठक प्रत्येक दो वर्ष में होती है।
 - ☛ इसका 12वाँ सम्मेलन कजाकिस्तान की अध्यक्षता में कोविड के कारण वर्ष 2022 को जेनेवा में संपन्न हुआ।

- ☛ 13वाँ सम्मेलन 2024 में अबुधावी में होगा।
 - **अन्य तथ्य**
 - ☛ WTO में कृषि व्यापार पर विकसित तथा विकाशील देशों के बीच उत्पन्न समस्याओं तथा व्यापार पर सब्सिडी से पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर सब्सिडी को पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है—
 - 1. **ग्रीन बॉक्स**
 - ☛ इस सब्सिडी पर कोई रोक नहीं है। यह 'गुड सब्सिडी' की श्रेणी में आता है।
 - 2. **ब्लू बॉक्स**
 - ☛ इस पर भी ज्यादा विवाद नहीं है परन्तु इस सब्सिडी की सीमा निर्धारित है।
 - 3. **अम्बर बॉक्स**
 - ☛ यह व्यापार प्रभावित करने वाली सब्सिडी कहलाती है। इस पर रोक या कम करने पर लगातार चर्चा हो रही है।
 - 4. **डी. मिनीमिस सब्सिडी**
 - ☛ विकासशील 10% तथा विकसित 5% तक सहायता दे सकते हैं।
 - 5. **रेड बॉक्स**
 - ☛ इसमें शामिल मदों को कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती है।
- Note:—** WTO संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। WTO के वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओकोन्जो-इवेला हैं।

अंकटाड (UNCTAD)

- **स्थापना**
 - ☛ संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं आर्थिक विकास पर अधिवेशन (United Nation Conference on Trade and Development) की स्थापना 1964 में किया गया।
 - ☛ यह संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा स्थापित किया गया है।
- **मुख्यालय**
 - ☛ जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड)।
- **सदस्य**
 - ☛ 195 सदस्य हैं। इसे UNO का स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
- **सम्मेलन**
 - ☛ इसके अब तक 15 सम्मेलन हो चुके हैं।
 - ☛ चार वर्ष पर सामान्यतः सम्मेलन बुलाया जाता है।
 - ☛ प्रथम सम्मेलन 1964 में जेनेवा में हुआ था।
 - ☛ अंकटाड का 14वाँ सम्मेलन जुलाई 2016 में कीनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ, जबकि 15वाँ सम्मेलन 2021 में बारबाडोस में हुआ।
 - ☛ इसके सभी सम्मेलनों में IMF को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

➤ **महानिर्देशक**

- ☞ रेबेका ग्रिनस्पैन (कोस्टारिका)

Note :- अंकटाड प्रत्येक वर्ष World Investment and Trade के संदर्भ में रिपोर्ट जारी करती है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय संघ

➤ **यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना**

- ☞ 1957 रोम की संधि के अंतर्गत। संस्थापक सदस्यों में फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, जर्मनी, इटली एवं नीदरलैंड हैं।
- ☞ यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 की मास्ट्रिच की संधि द्वारा हुई। वर्तमान में 27 सदस्य हैं। (ब्रिटेन अब इसका सदस्य नहीं है।)

➤ **मुख्यालय**

- ☞ ब्रुसेल्स (बेल्जियम)।

यूरोपीय समुदाय के प्रमुख अंग-

1. यूरोपीय परिषद्

- ☞ इसे यूरोपीय संघ का प्रशासनिक अंग कहते हैं। प्रत्येक सदस्य देश से एक मंत्री इस परिषद् का सदस्य होता है। अध्यक्षता क्रमिक रूप से परिवर्तित होती रहती है।

2. यूरोपीय आयोग

- ☞ यूरोपीय परिषद् के कार्यों में सहायता करना तथा संधि तथा इसके नियमों का अनुपालन करवाना।

3. यूरोपीय संसद

- ☞ प्रत्येक पांच वर्ष के चुनाव में सदस्य देशों के निर्वाचक मण्डल यूरोपीय संसद के सदस्य निर्वाचित कहते हैं।

4. यूरोपीय मुद्रा (यूरो)

- ☞ 1 नवम्बर, 1993 में लागू। मास्ट्रिच संधि यूरो करेंसी के उदय की बुनियाद बनी।

ब्रिक्स बैंक (BRICS Bank) या न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank)

➤ **स्थापना**

- ☞ जुलाई, 2014 में ब्रिक्स देशों- ब्राजील, रूस, इण्डिया, चाइना तथा साऊथ अफ्रीका का सम्मेलन ब्राजील के फोर्टालिजा में हुआ। इसी फोर्टालिजा घोषणा में न्यू डेवलपमेंट बैंक की **अधिकारिक नाम के साथ** घोषणा की गई। 21 जुलाई, 2015 को बैंक ने कार्य प्रारंभ किया।

➤ **अध्यक्ष**

- ☞ डिल्मा रूसेफ।

➤ **सदस्य देश**

- ☞ 9 (9वां सदस्य मिस्र)।

➤ **मुख्यालय**

- ☞ शंघाई (चीन)।

- ☞ 14वां BRICS सम्मेलन, 2022 का आयोजन चीन के शियामेन में हुआ था।

- ☞ 15वें BRICS सम्मेलन, 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है।

ट्रांस पैसिफिक भागीदारी (TPP)

➤ **स्थापना**

- ☞ 5 अक्टूबर, 2015 को 12 पैसिफिक राष्ट्रों तथा ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैण्ड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका तथा वियतनाम ने ट्रांसपैसिफिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किये।

➤ **अन्य तथ्य**

- ☞ TPP के 12 सदस्यों की वैश्विक जी.डी.पी. में 40% का योगदान है तथा वाणिज्य व्यापार में 60% की हिस्सेदारी है।
- ☞ यह उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र (NAFTA) से भी बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा।

Note :- अमेरिका के इस समझौते से बाहर हो जाने के बाद यह समझौता अपने मूलस्वरूप में क्रियान्वित नहीं हो पाया।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD)

The Organisation for Economic Co-operation and Development

➤ **स्थापना**

- ☞ 1948 में मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में बना। प्रारंभ में पेरिस सम्मेलन में इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग बनाया गया। बाद में 1961 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन कर दिया गया।

➤ **सदस्य**

- ☞ वर्तमान में इसके 37 सदस्य हैं। (37वां कोलंबिया)

➤ **मुख्यालय**

- ☞ पेरिस (फ्रांस) में है।

आसियान (ASEAN)

➤ **स्थापना**

- ☞ आसियान (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ या Association of South East Asian Nation) की स्थापना बैंकाक घोषणा के तहत 8 अगस्त, 1967 में हुआ।

➤ **सदस्य**

- ☞ 11 सदस्य। इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम तथा पूर्वी तिमोर।

➤ **मुख्यालय**

- ☞ जकार्ता (इण्डोनेशिया)
- ☞ आसियान 43वां (2023) सम्मेलन जकार्ता में सम्पन्न हुआ है।

- इसमें महासचिव के पद सभी सदस्य देशों को प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाता है।

एपेक (APEC) Asia-Pacific Economic Cooperation

- **स्थापना**
- इशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना नवम्बर 1989 में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर हुई थी।
- **सदस्य**
- 21 (21वां वियतनाम)।
- भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है।
- **उद्देश्य**
- इसके प्रमुख लक्ष्य को 'बोगोर लक्ष्य' कहा जाता है, जिसमें एशिया प्रशांत देशों के मध्य मुक्त एवं खुला व्यापार एवं निवेश शामिल है।
- **सचिवालय**
- इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थापित है।

दक्षेस (SAARC)

- **स्थापना**
- दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Co-operation-SAARC) की स्थापना ढाका में 1985 में हुई थी।
- **सदस्य**
- भारत, एशियाई, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल तथा बांग्लादेश एवं मालदीव है।
- इसका आठवां सदस्य अफगानिस्तान है।
- **मुख्यालय**
- काठमाण्डू (नेपाल)
- **उद्देश्य**
- दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना।

नाफ्टा (NAFTA)

- **उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (North American Pre Trade Agreement)**
- इसे 1994 में अधिनियमित किया गया।
- यह अमेरिका, कनाडा तथा मेक्सिको के बीच एक व्यापार समझौता है तथा निवेश के लिए नियम निर्धारित करता है।
- इन समझौतों के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की दुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया।
- ट्रेडमार्क, पेटेन्ट और करेन्सी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार सम्बंधी काफी सुगम नियम बनाए गए।

साफ्टा (SAFTA)

- **South Asian Preferential Trading Agreement (दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता)**
- 7 दिसम्बर, 1995 में शुरू हुआ। 1 जनवरी, 2007 को लागू हुआ।
- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की मुक्त व्यापार व्यवस्था है।
- यह समझौता 2006 ई. में लागू हुआ।
- **SAFTA पर हस्ताक्षरकर्ता देश-**
- (i) मालदीव (ii) श्रीलंका
- (iii) भारत (iv) पाकिस्तान
- (v) अफगानिस्तान (vi) नेपाल
- (vii) भूटान (viii) बांग्लादेश।

ओपेक (OPEC)

- **स्थापना**
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries) की स्थापना बगदाद में 1960 में किया गया।
- **सदस्य**
- 13
- Note :-** कतर एवं इक्वाडोर अब इसका सदस्य देश नहीं हैं।
- **मुख्यालय**
- वियना (ऑस्ट्रिया)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) Shanghai Cooperation Organisation

- यह एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है।
- **स्थापना**
- 2001 में, नवगठित शंघाई सहयोग संगठन वर्ष 2002 में इसके दूसरे शिखर सम्मेलन में औपचारिक अंतराष्ट्रीय संगठन बना।
- **सदस्य**
- अभी हाल ही में इरान को पूर्ण सदस्य बनाने के साथ इसकी सदस्य संख्या 9 हो गयी है।
- इसकी दो अधिकारिक भाषाएं **चीनी एवं रूसी** हैं।
- **इब्सा (IBSA) India Brazil South Africa)**
- ब्राजीलिया घोषणा के साथ भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का इब्सा संगठन 6 जून, 2003 में बना। इसका प्रथम सम्मेलन ब्राजील में 2006 को हुआ तथा 7वां सम्मेलन नई दिल्ली में 2015 में संपन्न हुआ है।

बिस्सटेक (BIMSTEC)➤ **स्थापना**

- ☛ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation यह पहले बिस्टेक (BISTEC) के नाम से जाना जाता था। म्यांमार के शामिल होने से यह

बिम्सटेक (BIMSTEC) बना है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक सम्मेलन में हुई।

➤ **सदस्य**

- ☛ बांग्लादेश, इण्डिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैण्ड, नेपाल तथा भूटान इसके सदस्य हैं।

□□□



भारतीय खाद्य निगम (FCI) Food Corporation of India)

- ☞ इसकी स्थापना 1964 ई० में हुई थी।
- ☞ कृषि उत्पादन के बाद रख-रखाव की जिम्मेदारी FCI की होती है।
- ☞ यह पूरे देश भर में खाद्यानों की खरीद बिक्री और वितरण भी करता है।
- ☞ यह देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- ☞ किसानों द्वारा प्रर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए MSP देता है।
- ☞ यह उचित नीतियों और बफर स्टॉक के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- ☞ सार्वजनिक वितरण दुकान (PDS) के माध्यम से विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करना।

बफर स्टॉक (Buffer Stock)

- ☞ किसी भी सीजन में फसलों का उत्पादन जब अधिक हो जाता है तो FCI बहुत मात्रा में अनाज खरीद कर Stock कर लेती है। ऐसे Stock को Buffer Stock कहते हैं।
- **CAPART (Council of Advancement of People's Action and Rural Technology)**
 - ☞ यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करती है।
- **ICAR (Indian Council of Agriculture Research)**
 - ☞ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुई थी।
- **IFFCO (Indian Farmer Fertilizer Cooperative Ltd.)**
 - ☞ यह विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। इसकी स्थापना 03 नवम्बर 1967 को नई दिल्ली में हुआ था।
- **NAFED (National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India)**
 - ☞ इसकी स्थापना 1974 में की गई है। इसका कार्य कृषि ऋण को बढ़ाना है।

➤ NFSA (National Food Security Act)

- ☞ आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितम्बर 2013 में पारित किया गया था।

➤ भारत माला परियोजना

- ☞ यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नये राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाता है जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाला विकास परियोजना वालों को शामिल किया गया है।

➤ सागर माला परियोजना

- ☞ इस परियोजना के तहत भारत में जितने भी बंदरगाह हैं। उन्हें आधुनिक तथा Automatic किया जा रहा है।

➤ DFC (Dedicate Freight Corridor)

- ☞ यह उच्च गति और ऊँच क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेलमार्ग होता है। जिसे विशेष तौर पर माल एवं वस्तुएं के परिवहन हेतु बनाया जाता है।

➤ Logistic Park

- ☞ Logistic Park भारत सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल है जिसका नेतृत्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत National Highway Logistic Management Ltd. और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, Hub and Multi Model Logistic Park विकसित करने के लिए करता है। इस पार्क से हवाई सड़क, रेल और जल मार्ग से जुड़ने से लोगों का आवागमन होने के साथ-साथ सामानों का परिवहन भी हो सकेगा। इस पार्क को केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है।

➤ Mega Food Park

- ☞ मेगा फूड पार्क यानि एक बड़ा Plant, एक ऐसी मशीनरी जहाँ कृषि उत्पादित फसल, फल, सब्जियों की सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था हो जहाँ उन Product की Processing की जा सके, उनसे Market के Demand के मुताबिक Product तैयार की जा सके।